एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ

जून 2013
खंड XXVII अंक II

इस अंक में

6 2012-13 में भारत में एफडीआई अंतर्वाह का मूल्यांकन

7 एक्ज़िम बैंक की ऋण व्यवस्थाएं

8 पिछली तिमाही

9 एक्ज़िम बैंक द्वारा 2012-13 में जबर्दस्त कारोबार वृध्दि दर्ज की गई

10 सर्जनात्मक उद्योग : अनुकरणीय समुत्थान-शक्ति का प्रदर्शन

11 भारतीय होम टेक्सटाइल उद्योग : दिन दूनी रात चौगुनी वृध्दि

12 अर्जेंटीना में निवेश अवसर

13 एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप तथा साहित्य समीक्षा

14 देशों का सूक्ष्मावलोकन

15 मुद्रा प्रवृत्तियां

16 विदेश व्यापार नीति 2009-14 : वार्षिक अनुपूरक 2013-14 की प्रमुख विशेषताएं

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

सार्क में भारत की वचनबध्दता

दिसंबर 1985 में सात दक्षिण एशियाई देशों-श्री लंका, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश- ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) की औपचारिक रूप से स्थापना करते हुए चॉर्टर अंगीकार किया । 2007 में संगठन में अफगानिस्तान के शामिल हो जाने से सार्क के सदस्यों की संख्या आठ हो गई । सार्क सदस्यों का सहयोग अन्य के साथ-साथ कृषि एवं ग्रामीण, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नति (संवर्धन) (कल्चर), ऊर्जा, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था तथा व्यापार, वित्त, निधीयन व्यवस्था, मानव संसाधन विकास, गरीबी उन्मूलन, व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क, सुरक्षा पहलू, सामाजिक विकास, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संचार तथा पर्यटन के क्षेत्र में रहा है । ढाका में अप्रैल 1993 में हस्ताक्षरित सार्क अधिमानी व्यापार करार (साप्टा) ने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) पर करार का मार्ग प्रशस्त किया, 4 से 6 जनवरी 2004 के दौरान इस्लामाबाद में आयोजित बारहवें सार्क सम्मेलन के दौरान सभी सदस्य राज्यों द्वारा साफ्टा पर हस्ताक्षर किये गए और यह 1 जनवरी, 2006 से प्रभावी है ।

सार्क के साथ भारत के गहराते संबंध इसके द्विपक्षीय व्यापार में सतत् तेजी में परिलक्षित होते हैं । सार्क के साथ भारत का कुल व्यापार 2002-03 के 3 बिलियन अमरिकी डॉलर हो गया । पिछली पंच-वर्षीय अवधि (अर्थात 2008-09 से 2012-13) के दौरान निर्यात 15.6 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा, जबकि आयात में 10.9 प्रतिशत की औसत दर से वृध्दि हुई **(तालिका 1)**

बांग्लादेश सार्क में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; उसके बाद श्री लंका, नेपाल तथा पाकिस्तान का स्थान है । भारत ने नेपाल, भूटान तथा श्री लंका के साथ मुक्त व्यापार करार (एफटीए) और अफगानिस्तान के साथ अधिमान्य व्यापार करार पर हस्ताक्षर करके अपने पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाया है । भारत ने क्षेत्र के व्यापार को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय रूप से तथा साफ्टा के अंतर्गत कई कदम उठाये हैं । 2011 में पाकिस्तान द्वारा भारत को सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का दर्जा दिया जाना एक प्रमुख उपलब्धि है जो अंतर-सार्क व्यापार का उत्प्रेरक है । भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा श्री लंका से माल की शुल्क मुक्त पहुँच की अनुमति देता है ।

सार्क क्षेत्र को भारत का निर्यात भारत के वैश्विक निर्यात का 4.9 प्रतिशत रहा । 2012-13 में सार्क को भारत के निर्यात समूह में कुछ प्रमुख वस्तुओं में अन्य के साथ-साथ कॉटन, जिसका वर्ष में कुल निर्यात में 14.5 प्रतिशत हिस्सा रहा, खनिज ईंधन, तेल तथा आसवन उत्पाद, रेलवे से भिन्न वाहन, अनाज, लौह एवं इस्पात, मशीनरी तथा उपकरण शामिल थे **(चार्ट 1)** । बांग्लादेश 2012-13 में कॉटन के लिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है, इसके बाद पाकिस्तान तथा श्री लंका का स्थान है । नेपाल सार्क क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है और वैश्विक रूप से 17 वाँ सबसे बड़ा गन्तव्य स्थान है । बांग्लादेश अनाजों, मुख्यतः गेहूँ, मक्का तथा चावल के भारतीय निर्यात का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य स्थान और मशीनरी एवं उपकरणों का 10 वाँ सबसे बड़ा गंतव्य स्थान भी है । श्री लंका रेलवे को छोड़कर वाहनों के भारतीय वैश्विक निर्यात का चौथा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान और मशीनरी एवं उपकरणों के लिए 17 वाँ सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है । बांग्लादेश भारत के लिए 15 वाँ सबसे बड़ा और श्री लंका 21 वाँ सबसे बड़ा निर्यात बाजार है ।

हालांकि, हाल के वर्षों में क्षेत्र को भारत के निर्यात का प्रदर्शन अच्छा रहा है, सार्क से भारत का आयात 2012-13 में कुल आयात के

तालिका 1: सार्क के साथ भारत का व्यापार (मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सार्क को भारत का निर्यात	8,567.1	8,390.7	11,659.2	13,296.5	14,805.1
सार्क से भारत का आयात	1,817.9	1,657.3	2,173.4	2,607.4	2,647.8
सार्क के साथ भारत का कुल व्यापार	10,385.0	10,048.0	13,832.6	15,903.9	17,452.9

स्त्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1 : सार्क को भारत के प्रमुख निर्यात, 2012-13

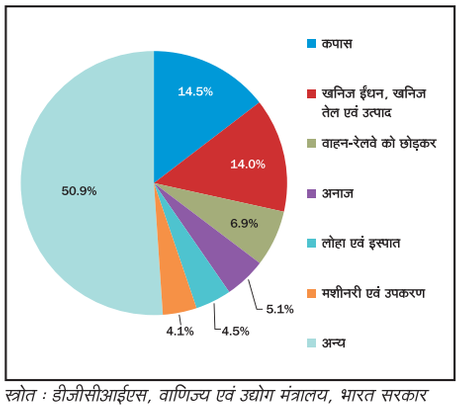

स्रोत : डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

1 प्रतिशत से कम रहा है जिसका मुख्य कारण क्षेत्र में सीमा-पार माल का परिवहन करते समय उपगत उच्च लेन-देन लागत है । वर्ष 2012-13 में सार्क क्षेत्र से मुख्य आयात में अन्य के साथ-साथ फल तथा गिरी, लौह एवं इस्पात, तांबा तथा वस्तुएं, कॉफी, चाय तथा मसाले, वनस्पतिक टेक्साइल रेशे, टेक्सटाइल वस्तुएं शामिल हैं । **(चार्ट 2)**

बांग्लादेश, नेपाल तथा श्री लंका का 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रीय व्यापार और वैश्विक व्यापार का अधिकांश हिस्सा भारत के साथ है ।

भारत-सार्क निवेश संबंध

अप्रैल 2000-मार्च 2013 के दौरान सार्क क्षेत्र से भारत में संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 36.9 मिलियन अमरिकी डॉलर (भारत के कुल का 0.02 प्रतिशत) रहा । श्रीलंका 29.4 मिलियन अमरिकी डॉलर

चार्ट 2 : सार्क से भारत की मुख्य आयात मदे

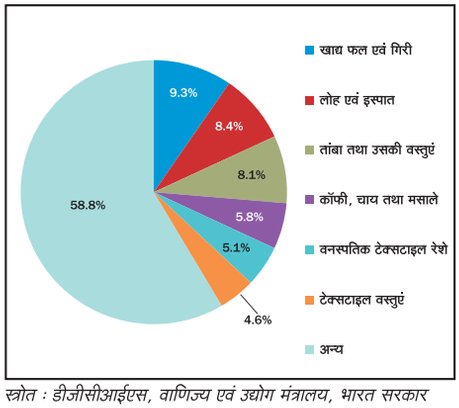

स्रोत : डीजीसीआईएस, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

मूल्य के एफडीआई अंतर्वाह के साथ सार्क क्षेत्र में भारत के वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह के लिए सबसे बड़ा स्त्रोत है; इसके बाद मालदीव (5.5 मिलियन अमरिकी डॉलर) तथा नेपाल (1.9 मिलियन अमरिकी डॉलर) का स्थान रहा ।

भारत में कुछ प्रमुख श्री लंकाई निवेशों में सिलोन बिस्कुट (मुंची ब्रांड), कारसन्स क्युम्बरबैच (कैरिसबर्ग), ब्रांडिक्स (लगभग 1 मिलियन अमरिकी डॉलर-विभाग में एक गार्मेंट सिटी की स्थापना के लिए), मैस होल्डिंग्स, जॉन कील्स, हेलेज़ तथा आइलकेन स्पेंस (होटल्स) शामिल हैं। सेवा उद्योग से माल परिवहन सेवा और संभार-तंत्र क्षेत्र में भी निवेश हैं ।

सार्क क्षेत्र में संचयी भारतीय समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) अप्रैल 1996-मार्च 2013 के दौरान 1.5 बिलियन अमरिकी डॉलर रहा जो भारत के वैश्विक बहिर्वाह का 0.8 प्रतिशत है । श्री लंका तथा बांग्लादेश सार्क क्षेत्र को भारत के बहिर्वाह के लिए शीर्ष दो गंतव्य स्थान रहे हैं ।

2012-13 के दौरान, सार्क क्षेत्र में भारत का ओडीआई 280.3 मिलियन अमरिकी डॉलर रहा, इसके बाद बांग्लादेश और नेपाल का स्थान रहा । **(तालिका 2) :**

तालिका 2 : 2012-13 के दौरान सार्क में भारतीय समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश

देश	बहिर्वाह (मि.अमरिकी डॉलर)
श्री लंका	227.3
बांग्लादेश	28.5
नेपाल	17.5
भूटान	6.7
अफगानिस्तान	0.2
मालदीव	0.2
कुल	280.3

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

श्री लंका क्षेत्र के कुल के 81.1 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है । श्री लंका निवेश बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2012 में भारत श्री लंका में चौथा सबसे बड़ा निवेशक था । गोदरेज, बजाज, टाटा तथा डाबर जैसी भारतीय कंपनियां श्री लंका में लोकप्रिय नाम हैं । आगामी वर्षों में श्री लंका में निवेश की योजना बनाने वाली भारतीय कंपनियों में आईटीसी लि., टाटा हाउसिंग, श्री रेणुका सुगर्स आदि शामिल हैं । कई शीर्ष भारतीय कंपनियों ने श्री लंका में इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, सेवा तथा निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है ।

बांग्लादेश भारतीय ओडीआई के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य स्थान है जिसका सार्क क्षेत्र को कुल बहिर्वाह में 10.1 प्रतिशत हिस्सा रहा । भारतीय रुचि के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि आधारित, टेक्सटाइल, रासायनिक उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सेवा उद्योग शामिल हैं । बांग्लादेश को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में भारतीय निवेश दुगुना हो जाएगा । बांग्लादेश कृषि प्रसंस्करण, आटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रसायन, प्लास्टिक, हल्की इंजीनियरिंग, सिरॉमिक्स, रत्न एवं आभूषण, औषधि तथा आईटी जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ संयुक्त उद्यम के निर्माण का प्रयास कर रहा है । बांग्लादेश में मौजूद कुछ भारतीय कंपनियों में भारती एयरटेल, पेसीफिक अपैरेल्स लि., अरविंद फैशन लि., तथा उत्तरा फूड्स एंड फीड्स प्रा. लि. शामिल हैं ।

भारत नेपाल के लिए विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्त्रोत है । नेपाल में भारतीय कारोबार उद्यम विनिर्माण, सेवा (बैंकिंग, बीमा, शुष्क पत्तन, शिक्षा तथा दूरसंचार), बिजली क्षेत्र तथा पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैले हैं । नेपाल में परिचालनरत अग्रणी भारतीय कंपनियों में आईटीसी, डाबर इंडिया, हिन्दुस्तान लीवर, बीएसएनएल, टीसीआईएल, एमटीएनएल, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, एशियन पेंट्स, कॉनकर, जीएमआर इंडिया, आईएल एंड एफएस, मणिपाल ग्रुप, मिट ग्रुप होल्डिंग्स, नुपुर इंटरनेशनल, ट्रान्सवर्ल्ड ग्रुप, पटेल इंजीनियरिंग, भीलवाड़ा एनर्जी, भूषण ग्रुप तथा बिड़ला कॉर्पोरेशन शामिल हैं । हाल के समय में नेपाल ने हाइड्रोपावर तथा आटोमोबाइल क्षेत्र परियोजनाओं में भारतीय निवेश आमंत्रित किया है ।

वर्तमान में, भारत भूटान के हाइड्रोपावर क्षेत्र में प्रमुख पहुँच रखने वाला एकमात्र देश है। हाइड्रोपावर द्विपक्षीय सहयोग का एक प्रमुख क्षेत्र है। भारतीय सहायता से विकसित तीन हाइड्रोपावर परियोजनाओं में 1020 मेगावॉट टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 336 मेगावॉट चुखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 60 मेगावॉट कुरीद्दु हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शामिल है ।

भारत 1965 में मालदीव के स्वतंत्र होने के बाद उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में है । 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक में मालदीव में भारतीय विकासात्मक सहयोग प्रमुख विकासपरक तथा संस्थागत परियोजनाओं पर केन्द्रित रहा । भारतीय स्टेट बैंक द्वीप रिजॉर्ट के संवर्धन, समुद्री उत्पादों के निर्यात और कारोबारी उद्यमों के लिए ऋण सहायता प्रदान कर 1974 से ही मालदीव के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। ताज ग्रुप ऑफ इंडिया मालदीव में ताज एक्सोटिका रिजॉर्ट एंड स्पा तथा विवंता कोरल रीफ रिजॉर्ट का परिचालन करता है । नवंबर 2009 में, भारत की सुजलॉन एनर्जी ने मालदीव के दक्षिण प्रांत में 40 मिलियन अमरिकी डॉलर के निवेश पर 25 मेगावॉट का एक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये और दिल्ली की श्री एज्युकेयर ने घियास्सुद्दीन स्कूल के प्रबंध का अधिग्रहण करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जो मालदीव सरकार की निजीकरण नीति के अंतर्गत ऐसी पहली पहल है । जुलाई 2010 में भारत की बोम्मीडाला इंफ्रास्ट्रक्चर ने ऊपरी दक्षिण प्रांत में 25 मेगावॉट की सौर-ऊर्जा परियोजना के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये ।

सार्क क्षेत्र में भारत की अन्य वचनबध्दताएं

अफगानिस्तान को भारत की वचनबध्द सहायता लगभग 2 मिलियन अमरिकी डॉलर है जो इसे अफगानिस्तान में पांचवां सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बनाता है । भारत के कार्यक्रम में चार व्यापक क्षेत्र शामिल हैं - इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, मानवीय सहायता, लघु एवं समुदाय आधारित विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा एवं क्षमता विकास ।

भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है । भारत सरकार ने 10 वीं पंचवर्षीय योजना (2008-2013) के लिए ₹ 3400 करोड़ मूल्य की वित्तीय सहायता का वचन दिया है जिसमें परियोजना आबध्द सहायता, प्रोग्राम अनुदान तथा लघु विकास परियोजनाएं शामिल हैं । भारत सरकार ने 1 मिलियन टन की सीमेंट परियोजना की स्थापना के लिए भी वचन दिया है, जो निर्माणाधीन है । भारत सरकार ने भूटान को रुपया चलनिधि संकट से उबारने के लिए भूटान रॉयल सरकार को 1000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा भी प्रदान की है । इस सुविधा के अंतर्गत भारत सरकार भूटान रॉयल सरकार को 5.0 प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर भूटान रॉयल सरकार को ऋण प्रदान करती है और यह सुविधा 5 वर्ष के लिए वैध है ।

भारत की एनटीपीसी ने 1.5 बिलियन अमरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर 1320 मेगावॉट के कोयला आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए बांग्लादेश की बीपीडीपी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके 2016 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

भारत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास और शिक्षा के क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरु करके नेपाल सरकार के विकास प्रयासों में योगदान देता है । श्री लंका में भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन संयोजकता तथा लघु एवं मध्यम उद्यम विकास जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु विकास परियोजनाओं की सहायता करता है ।

इसके अलावा, आईटीईसी, टीसीएस ऑफ कोलम्बो प्लान, आईसीसीआर, आयुष, राष्ट्रमंडल, सार्क के अंतर्गत छात्रवृत्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आईओआर-एआरसी छात्रवृत्ति / फेलोशिप योजनाएं अन्य सार्क सदस्यों को प्रदान की जा रही हैं ।

सार्क में एक्ज़िम बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) सार्क क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार तथा निवेश संबंधों को संवर्धित करने तथा सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के वित्तपोषण, सलाहकारी तथा सहायता कार्यक्रम चलाता है। सार्क क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए एक्ज़िम बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा कई संयुक्त उद्यमों को सहायता प्रदान की है : श्री लंका में टेक्सटाइल (अरविंद मिल्स लि.), औषधि (कैडिला फार्मास्युटिकल्स लि.), इस्पात (भुवालका स्टील इंडस्ट्रीज लि.), ग्लास (गुजरात ग्लास लि.), क्षेत्र; बांग्लादेश में इलेक्ट्रिकल (विजय इलेक्ट्रिकल्स लि.), क्षेत्र; नेपाल में इंजीनियरिंग माल (ओडिशा इंजीनियरिंग लि.) तथा टेक्सटाइल (श्री सरिता सिंथेटिक्स लि.) क्षेत्र ।

31 मार्च, 2013 को एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश पर सार्क क्षेत्र के सदस्यों को 2.3 बिलियन अमरिकी डॉलर मूल्य की ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं । इनमें शामिल हैं : बांग्लादेश को विभिन्न प्रयोजनों के लिए 40 मिलियन अमरिकी डॉलर, मालदीव को आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 40 मिलियन अमरिकी डॉलर, नेपाल को इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 350 मिलियन अमरिकी डॉलर और श्री लंका को भारत से उपकरणों की खरीद के लिए तथा रेलवे लाइनों के पुनरुत्थान तथा उन्नयन के लिए 1,0682 मिलियन अमरिकी डॉलर ।

सार्क क्षेत्र में एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कुल चालू परियोजनाएं 10,518 करोड़ रुपये मूल्य की हैं । इनमें भूटान में 8006 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं, बांग्लादेश में 1131 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं, अफगानिस्तान में 976 करोड़ रुपये और श्री लंका में 405 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं शामिल हैं ।

कारोबार अवसर तथा प्राप्त संविदाएं

यथा जून 2013 को नई परियोजनाएं

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी
हनोई पॉवर कॉर्पोरेशन निविदा विभाग नं. 69 दिन्ह टीन होन, कीम जिला हनोई सिटी, वियतनाम **संपर्क :** टेली. : +84 4 22200852 फैक्स : +84 4 22200853 ईमेल : dauthau.evnhanoi@gmail.com	**वितरण कार्यकुशलता परियोजना** परियोजना में उप-परियोजना 110 केवी गिया लैम 2 उप-स्टेशन और ओवरहेड लाइन के लिए उप-स्टेशन उपकरणों तथा सामग्री की आपूर्ति शामिल है ।	**विश्व बैंक** 449 मिलियन यूएस डॉलर
दि यूगांडा इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लि. (यूईटीसीएल) पो.बॉ.नं. 7625, प्लॉट 10, हनिंगटन रोड कम्पाला यूगांडा **संपर्क :** प्रधान प्रापण अधिकारी टेली. : +256 414 233 433/4 फैक्स : +256 414 341 789 ईमेल : procurement@uetcl.com	**विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना** परियोजना में निम्न के लिए संविदा शामिल है :- • लॉट 1 : कवांडा - मसाका 220 केवी पारेषण लाइन का निर्माण; • लॉट 2 : कवांडा उप-स्टेशन का उन्नयन तथा विस्तार • लॉट 3 : मसाका में नये उप-स्टेशन का निर्माण तथा बरारा उप-स्टेशन का उनयन	**विश्व बैंक** 120 मिलियन यूएस डॉलर
हवाई अड्डा 'एलेग्जेंडर दि ग्रेट' - स्कोपजे पो.बॉ.नं. 9 1043 पेट्रोवेक मेसेडोनिया **संपर्क :** श्री. निकोलेट टैगारिंस्की टेली. : +389 2 3148 100 +389 2 3251 800 ईमेल : nikolet.tagarinski@mnavigation.mk	**विमानन सेवा प्रणाली का उन्नयन** • तकनीकी परिचालन कक्ष सहित नये विमानन यातायात प्रबंध प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग • कई संचार सुविधाओं का उन्नयन, तथा • प्रापण तैयारी तथा परियोजना कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएं	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 13.35 मिलियन यूरो
नेशनलना इलेक्ट्रिचेस्का कंपनिया (एनईके), ईएडी 5, 'वेस्टेट्ज' स्ट्रीट 1040 सोफिया बुल्गेरिया **संपर्क :** श्री जुली लैम्ब्रीव फैक्स : +359 2 986 12 88 ईमेल : grant-hydro@nek.bg	**बिजली पारेषण नेटवर्क परियोजना का पुनरुत्थान तथा विस्तार** परियोजना के कार्यक्षेत्र में 110 केवी उच्च वोल्टेज उपकरण, डिस्कनेक्टर, सर्किट ब्रेकर, प्रवाह नियंत्रक, बिजली लाइन संरक्षण, दूरसंचार उपकरण, अनुषंगी उपकरण, नियंत्रण प्रणाली तथा अन्य एचपीपी उपकरणों तथा प्रणालियों की डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग शामिल है ।	**यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक** 5 मिलियन यूरो
काठमांडु घाटी तथा बीरगुंज-सिमरा कॉरिडोर वितरण प्रणाली पुनः प्रवर्तन तथा हानि में कमी परियोजना योजना एवं तकनीकी सेवा विभाग वितरण एवं उपभोक्ता सेवाएं पूर्वी दरबार मार्ग, काठमांडु नेपाल **संपर्क :** परियोजना प्रबंधक टेली. : +977 1 4153153 फैक्स : +977 1 4153155 ईमेल : neatscd@gmail.com	**ऊर्जा अभिगम तथा कार्यकुशलता सुधार परियोजना** नेपाल की ऊर्जा अभिगम तथा कार्यकुशलता परियोजना में विभिन्न लाइन सामग्रियों की आपूर्ति तथा सुपुर्दगी और लाइनों की संस्थापना शामिल है ।	**एशियाई विकास बैंक** 41.2 मिलियन यूएस डॉलर

देश/निष्पादक एजेंसी	परियोजना/संक्षिप्त कार्यक्षेत्र	निधीयन एजेंसी
निवारक स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन परियोजना **हेरेक बिल्डिंग** 11 वीं मंजिल, कमरा नं. 3, 4ए लांघा स्ट्रीट बदीन्ह जिला हनोई सिटी वियतनाम **संपर्क :** टेली. : +84 437724 906 फैक्स : +84 437724 908 ईमेल : adbytdp@vnn.vn	**निवारक स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन परियोजना** इस परियोजना में चार घटक हैं : (i) स्वास्थ्य निगरानी तथा प्राथमिकता स्वास्थ्य मुद्दे (ii) निवारक स्वास्थ्य सेवा को मजबूत बनाना (iii) मानव संसाधन विकास, तथा (iv) परियोजना प्रबंधक	**एशियाई विकास बैंक** 47.54 मिलियन यूएस डॉलर
केन्या इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कं. लि. कैपिटल हिल स्क्वॉयर, दूसरी मंज़िल च्युलू रोड, अपर हिल नैरोबी केन्या **संपर्क :** डॉ. जॉन एम. मैटिबो तकनीकी सेवा प्रमुख टेली. : +254 20 4956000 फैक्स : +254 20 4956010 ईमेल : jmativo@ketraco.co.ke	**नील भूमध्यवर्ती झील देशों के विद्युत ग्रिडों का अंतर-संयोजन (केन्या का हिस्सा)** परियोजना में लेसोस उप-स्टेशन से यूगांडा की सीमा तक 127 किमी. लम्बी 220 केवी डबल सर्किट ट्रान्समिशन लाइन का निर्माण शामिल है। नई 220 केवी ट्रान्समिशन लाइन लेसोस-टोरोरो मुख्यतः मौजूदा 132 केवी लेसोस-टोरोरो लाइन के समानांतर होगी।	**अफ्रीकी विकास बैंक** 245 मिलियन यूएस डॉलर
ऊर्जा जल तथा स्वच्छता प्राधिकरण एवेन्यु डु लैक हीमा, पो.बॉ. 537, किगाली रवांडा **संपर्क :** टेली. : +250 252573666 फैक्स : +250 252573802 ईमेल : lvwatsan2@ewsa.rw info@ewsa.rw	**लेक विक्टोरिया जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम-चरण II** परियोजना का उद्देश्य जल तथा स्वच्छता सेवाओं का प्रबंध करने वाली नई/मौजूदा संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। परियोजना में न्यागटारे न्यानजा तथा कयोन्जा कस्बों में मल चूषण ट्रकों तथा ठोस अवशिष्ट कम्पैक्टर ट्रकों की आपूर्ति हेतु संविदा शामिल हैं।	**अफ्रीकी विकास बैंक** 112 मिलियन यूएस डॉलर

भारतीय कंपनियों/परामर्शदाताओं द्वारा प्राप्त चुनिंदा संविदाएं

सर्जीक्वॉयन मेडेक्वीप प्रा. लि., सोनीपत	**विश्व बैंक** समूह द्वारा निधिक - नेपाल की दूसरी एचएनपी परियोजना के लिए छोटे अस्पताल उपकरण, फर्नीचर तथा ऑपरेटिंग लाइट की आपूर्ति हेतु संविदा।
एंजेलिक इंटरनेशनल लि., नई दिल्ली	**विश्व बैंक** समूह द्वारा निधिक - जाम्बिया की बिजली तक बर्धित अभिगम परियोजना के लिए चिबॉम्बो 132(88)33 केवी उपस्टेशनों के निर्माण तथा फिग ट्री के रीफर्बिशमेंट हेतु संविदा।
राइट्स लि., गुड़गांव	**विश्व बैंक** समूह द्वारा निधिक - केन्या की उत्तरी कॉरिडोर परिवहन सुधार परियोजना के लिए 50 वर्षीय परिवहन मास्टर प्लान के विकास हेतु परामर्शी सेवा।
न्यूकॉन स्विच गियर्स प्रा. लि., लुधियाना	**विश्व बैंक** समूह द्वारा निधिक - केन्या की ऊर्जा क्षेत्र सुधार परियोजना के लिए वितरण ट्रान्सफॉर्मरों की आपूर्ति हेतु संविदा।
सिप्ला लि., मुंबई	**विश्व बैंक** समूह ईथियोपिया की पोषण परियोजना के लिए औषधियों की आपूर्ति हेतु संविदा।
टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लि., फरीदाबाद तथा गैमन इंडिया लि. मुंबई का संयुक्त उद्यम	**अफ्रीकी विकास बैंक** समूह द्वारा निधिक - जिम्बाब्वे की जल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना के लिए पाँच स्टेशनों का पुनरुत्थान/फिर से सुसज्जित करना, प्रवाह नियंत्रण सहित अभिक्रिया कार्य की शीघ्र मरम्मत, रासायनिक बन्दी तथा पम्पिंग उपकरण, वितरण प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु संविदा।
हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कं. लि., मुंबई	**एशियाई विकास बैंक** द्वारा निधिक - भूटान की हरित विद्युत विकास परियोजन के लिए दगाछु हाइड्रोपावर परियोजना (सिविल कार्य) के निर्माण हेतु संविदा।
प्रीशिजन इंफ्राटेक लि., अहमदाबाद	**एशियाई विकास बैंक** द्वारा निधिक - नेपाल के गण्डक हाइड्रोपावर प्लांट में ट्रैश रैक सफाई मशीन की डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण, सुपुर्दगी, स्थापना तथा कमीशनिंग हेतु संविदा।

6 2012-13 में भारत में एफडीआई अंतर्वाह का मूल्यांकन

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को किसी देश की विनिर्यात तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक साधन माना जाता है । एफडीआई को सामान्यतः चालू खाता घाटे का वित्तपोषण करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रवाह का एक अत्यंत स्थिर घटक माना जाता है। इसके अलावा यह अदृश्य संसाधनों को बढ़ाता है, उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करता है, उत्पादन तकनीक की जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है और निर्यात को बढ़ावा देता है। हालांकि विदेशी निवेश के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ में अपेक्षाकृत संतुलित रहा है, इसने 1990 के दशक के प्रारंभ से अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अधिक उदारीकृत नीति दृष्टिकोण की और क्रमिक रूप से कदम बढ़ाना शुरू कर दिया ।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारत में एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह पूर्ववर्ती वर्ष के 35.1 बिलियन यूएस डॉलर से 38 प्रतिशत घटकर 22.4 बिलियन यूएस डॉलर रह गया। मासिक प्रवृत्तियां सुझाती हैं कि एफडीआई (ईक्विटी) अंतर्वाह में 2012-13 के दौरान जुलाई, सितंबर, अक्तूबर तथा जनवरी महिनों को छोड़कर अधिकांश महिनों में नकारात्मक वृध्दि दर्ज की गई है। अंतर्वाह सितंबर 2012 के दौरान 4.7 बिलियन यूएस डॉलर के उच्चतर स्तर पर रहा।

वर्ष के दौरान मॉरिशस सबसे बड़ा निवेशक था जिसका वर्ष के दौरान कुल निवेश में 42.5 प्रतिशत हिस्सा रहा। इसके बाद सिंगापुर (10.3 प्रतिशत), जपान (10.0 प्रतिशत) नीदरलैंड (8.3 प्रतिशत), यूके (4.8 प्रतिशत) तथा जर्मनी (3.8 प्रतिशत) का स्थान रहा । सिंगापुर पिछले वर्ष के दूसरे सबसे बड़े निवेशक यूके से आगे बढ़ते हुए वर्ष के दौरान दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा है ।

जहाँ तक क्षेत्रों में एफडीआई अंतर्वाह का संबंध है, वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय / कारोबार, आउटसोर्सिंग, आर एंडी, कुरियर, प्रौद्योगिकी परीक्षण तथा विश्लेषण सहित सेवा क्षेत्र ने 4.8 बिलियन यूएस डॉलर का सर्वाधिक एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह आकृष्ट किया । इसके बाद होटल तथा पर्यटन, आटोमोबाईल उद्योग तथा धात्विक उद्योग का स्थान रहा । **(चार्ट)**

चार्ट : 2012-13 में क्षेत्र-वार एफडीआई ईक्विटी अंतर्वाह

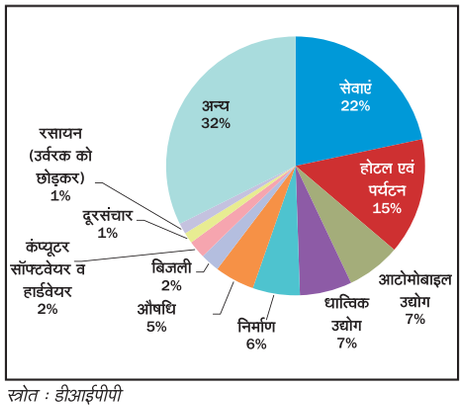

स्रोत : डीआईपीपी

वर्ष के दौरान एफडीआई अंतर्वाह में गिरावट के कारण आंतरिक तथा बाह्य कई कारक जैसे अनिश्चित वैश्विक परिदृश्य, ऊर्जा की अपेक्षाकृत उँची कीमतें, देशी माँग में मंदी, लगातार उच्च मुद्रास्फीति तथा पूंजी की उच्च लागत हो सकते हैं ।

तात्कालिक नीतिगत कार्रवाई

तथापि, गिरते एफडीआई के प्रत्युत्तर में सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न नीतिगत पहल-कार्य किये हैं। 2012-13 के दौरान एफडीआई नीति व्यवस्था में कई परिवर्तन किये गये। एकल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। (i) विदेशी निवेशक का ब्रांड का मालिक होना - यह निर्दिष्ट किया गया है कि अब से, सिर्फ एक अनिवासी संस्था / कंपनी (चाहे ब्रांड का स्वामी हो या अन्यथा) को ब्रांड मालिक के साथ विधित - युक्तियुक्त करार के माध्यम से विशिष्ठ ब्रांड के लिए एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार शुरु करने की अनुमति दी जाएगी और (ii) उत्पादों के मूल्य के कम से कम 30 प्रतिशत माल की सोर्सिंग भारतीय लघु उद्योगों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों तथा कारीगरों से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। 51 प्रतिशत से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध मे लागू । नागरिक विमानन क्षेत्र में, विदेशी एयरलाईनों को स्वतः / सरकारी मार्ग के अंतर्गत निर्धारित तथा गैर-निर्धारित उड़ान का परिचालन करनेवाली भारतीय नागरिक विमानन कंपनियों की पूंजी में 51 प्रतिशत तक एफडीआई से कुछ निर्दिष्ट शर्तों के अधीन 51 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत बिजली एक्सचेंजों 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी है। सरकार ने 75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश रखनेवाली और 50 मिलियन यूएस डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को परिचालनरत सहायक कंपनियों की संख्या पर किसी प्रतिबंध के बिना और अतिरिक्त पूंजी लाये बिना विशिष्ठ एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए अनुषंगी सहायक कंपनियों की स्थापना करने की अनुमती देने का निर्णय लिया है ।

एफडीआई अंतर्वाह को और सुगम बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2013 से सम्मलित एफडीआई नीति जारी की। नीति में भारत में एफडीआई अंतर्वाह के संबंध में जारी तथा लागू सभी प्रेस नोट / प्रेस विज्ञप्ति / स्पष्टीकरण / परिपत्र शामिल हैं ।

भावी संभावनाएं

हालांकि अद्यतन एफडीआई नीतियों का भारत में एफडीआई अंतर्वाह पर तात्कालिक प्रभाव दिखाई नहीं देता है, इनका प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने की उम्मीद है ।

भारत अब भी विश्व में शीर्ष निवेश गंतव्य स्थानों में है। एटी कियरने फॉरेन डॉयरेक्ट इन्वेस्टमेंट कांफिडेंस इंडेक्स 2013 के अनुसार, भारत को वैश्विक स्तर पर एफडीआई विश्व सूचकांक में पाँचवें स्थान पर रखा गया है। व्यापार तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड) की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2013 के अनुसार भारत 2012 में एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता को वैश्विक रैंकिंग में 15 वें स्थान पर है। उसी रिपोर्ट में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार भारत 2013-15 के दौरान सीमापार निगमों द्वारा निवेश के लिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आकर्षक गंतव्य स्थान बना हुआ है ।

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्योगों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) देने पर विशेष जोर दिया हैं। एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है जो उन देशों के क्रेताओं का भारत से आस्थगित ऋण शर्तों पर विकासपरक और बुनियादी संरचना, परियोजनाएं, उपकरण, माल सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं । साथ ही, भारतीय निर्यातक पोतलदान दस्तावेजों के आधार पर एक्ज़िम बैंक से पात्र मूल्य का भुगतान दायित्व-रहित आधार पर प्राप्त कर सकते हैं । एक्ज़िम बैंक स्वयं के अलावा भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है । जारी ऋण-व्यवस्थाओं में एक्ज़िम बैंक माल के पोतलदान पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य का 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्ते कि माल एवं सेवाओं के कुल संविदा मूल्य का कम-से-कम 75 प्रतिशत भारत से लिया जाए । एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों के लिए जोखिम रहित, दायित्व-रहित निर्यात वित्तपोषण का बेहतरीन विकल्प है ।

एक्ज़िम बैंक की वर्तमान मे 172 ऋण-व्यवस्थाएं परिचालनरत हैं, जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप, ओशिनिया तथा सीआईएस के 75 देशों को शामिल करते हुए 9.08 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण-राशि अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात वित्तपोषण के लिए उपलब्ध है। इन ऋण-व्यवस्थाओं ने अलग-अलग क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं के निर्यात को उत्प्रेरित किया है जिनमें कृषि, परिवहन, संचार विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा पारेषण, ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं। भारतीय परियोजना निर्यात वित्तपोषण के लिए प्रदान की जा रही ये ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देशों में विकास के साथ-साथ भारतीय विशेषज्ञता एवं परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। मुख्यतः विकासशील देशों को भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई ये ऋण-व्यवस्थाएं आज बाजार व्यापन का प्रभावी साधन बन गई हैं और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिकी देशों के अब तक बाजारों में प्रवेश का साधन है ।

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश पर और सहयोग से अप्रैल-जून 2013 तिमाही के दौरान निम्नलिखित ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की हैं :

➢ निकारगुआ सरकार को दो विद्युत उप-स्टेशनों के निर्माण के लिए भारत से उपकरणों की आपूर्ति के वित्तपोषण के लिए 10 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था;

➢ इथियोपिया सरकार को नई इथियो-दजीबाउटी रेल लाईन (असैता-टैडजौराह भाग) परियोजना के वित्तपोषण के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था। एक्ज़िम बैंक ने इसके पहले (क) विद्युत पारेषण तथा वितरण परियोजना (65 मिलियन यूएस डॉलर) के वित्तपोषण के लिए कुल 705 मिलियन यूएस डॉलर की छः ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की है ।

➢ जिम्बाबे सरकार को डेका पम्पिंग स्टेशन और नदी जल अंतर्ग्रहण प्रणाली के उन्नयन के वित्तपोषण के लिए 286 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था ।

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करे :

सुश्री गीता पूजारी
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक,
केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड,
मुंबई - 400 005

दूरभाष : (022) 22162073
(022) 22172310
फैक्स : (022) 22182460
ई-मेल : eximloc@eximbankindia.in

परियोजना निर्यात : एक्ज़िम बैंक की भूमिका

परियोजना निर्यात किसी देश के आर्थिक विकास का एक माप है। एक्ज़िम बैंक परियोजना निर्यात के संवर्धन के लिए समन्वयकर्ता तथा सुलभकर्ता की भूमिका अदा करता है और समुद्रपारीय औद्योगिक टर्न की परियोजनाओं, सिविल निर्माण संविदाओं, आपूर्तियों और तकनीकी एवं परामर्शी सेवा संविदाओं को शामिल करते हुए परियोजना निर्यात पर कार्यकारी समूह (आस्थगित भुगतान शर्तों पर या टर्न की परियोजना या सिविल निर्माण संविदा के निष्पादन में माल तथा सेवाओं के निर्यात संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित एक अंतर संस्थागत व्यवस्था, जिसमें एक्ज़िम बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ईसीजीसी शामिल हैं) के संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करता है ।

एक्ज़िम बैंक भारतीय परियोजना निर्यातकों को एक व्यापक वित्तपोषण पैकेज ऑफर करने के लिए सुसज्जित है जिसमें निधिक सहायता, परियोजना सम्बध्द गारंटी सुविधाएं और समुद्रपारीय परियोजनाओं के लिए अन्य देश से आयात के लिए उनकी ओर से साख-पत्र जारी करना शामिल है। भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने पर बैंक का प्रमुख जोर भारत सरकार के राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा (बीसी-एनईआईए) प्रोग्राम के अंतर्गत क्रेता-ऋण शुरू करने से बढ़ गया है । बीसी-एनईआईए एक अनोखी वित्तपोषण व्यवस्था है जो भारतीय निर्यातकों को दायित्व-रहित वित्तपोषण विकल्प का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करती है और विकासशील देशो में जिन्हें मध्यावधि या दीर्घावधि आधार पर आस्थागित ऋण की आवश्यकता होती है, पारंपरिक तथा नये बाजारों के लिए प्रभावी बाजार प्रवेश साधन के रूप में कार्य करती है ।

यथा 31 मार्च, 2013 को, बैंक द्वारा समर्थित ₹ 116,019 करोड़ (लगभग 21.37 बिलियन यूएस डॉलर) मूल्य की 293 परियोजना निर्यात संविदाएं 90 भारतीय कंपनियों द्वारा एशिया, अफ्रीका तथा सीआईएस के 68 देशों में निष्पादनाधीन थीं। निष्पादनाधीन इन परियोजनाओं में से 41 देशों में ₹ 20,682 करोड़ मूल्य की 163 परियोजनाएं एक्ज़िम बैंक की भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं ।

अप्रैल में सेवा निर्यात में 22.5 प्रतिशत की वृध्दि

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2013 में भारत का सेवा निर्यात 12.8 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो गत वर्ष की अनुरुपी अवधि के 10.5 बिलियन यूएस डॉलर से 22.5 प्रतिशत अधिक है। 2012-13 राजकोषीय वर्ष के दौरान सेवा-प्राप्तियां 145.7 बिलियन यूएस डॉलर रहीं, जबकि सेवाओं का आयात मूल्य 80.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा । अप्रैल 2013 में सेवाओं का आयात (भुगतान) एक वर्ष पूर्व 6.5 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 7.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा । देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 55.0 प्रतिशत है और राष्ट्रीय तथा राज्यों की आय, व्यापार प्रवाह, एफडीआई अंतर्वाह तथा रोजगार में योगदान की दृष्टि से यह एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में उभरा है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा सोने के आपात को प्रतिबंधित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वर्णाभूषण के निर्यातकों की वास्तविक जरुरतों को पूरा करने के लिए सिर्फ पारेषण आधार पर बैंकों द्वारा बुलियन के आयात को प्रतिबंधित करने के अपने प्रस्ताव को अधिसूचित किया है । सोने की माँग उपयोग, निवेश या सट्टेबाजी के लिए होती है । यदि कीमतें घटती हैं, तो माँग बढ़ सकती है, लेकिन निवेश तथा सट्टेबाजी माँग संतुलित रहेगी । भारतीय रिज़र्व बैंक की चिंता चालू खाता घाटे का प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता प्रबंधन और व्यापक उपभोक्ता संरक्षण है ।

चालू खाता घाटा जनवरी-मार्च तिमाही में घटा

राजकोषीय वर्ष 2012-13 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए भारत के भुगतान संतुलन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों की विज्ञप्ति मे कहा गया है कि तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा (कैड) कम होकर 18.1 बिलियन यूएस डॉलर या जीडीपी का 3.6 प्रतिशत रह गया है जो अपेक्षित स्तर और गत वर्ष की अनुरुपी अवधि के दौरान दर्ज किये गये 21.7 बिलियन यूएस डॉलर घाटे से कम है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि चालू खाता घाटा 2012-13 की तीसरी तिमाही में जीडीपी के 6.7 प्रतिशत के ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर से 2012-13 की चौथी तिमाही में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत हो गया है क्योंकि व्यापार घाटा कम हो गया है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि, चालू खाता घाटे में कमी मंद अर्थिक वृध्दि के परिणाम स्वरूप गैर-तेल तथा गैर-स्वर्ण आयात में गिरावट के कारण आयी है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात आय वापस जाने के समय में कटौती की

चालू खाता घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए देश में डॉलर आकर्षित करने के प्रयास में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के लिए बिक्री आय की वसूली अवधि को निर्यात की तारीख से 12 महीने से घटाकर 9 महीने कर दी है । निर्यातकों के लिए, निर्यात किये गये माल या सॉफ्टवेयर के पूरे मूल्य की प्रतिनिधित्व राशि की वसूली तथा भारत में प्रत्यावर्तन के लिए एक वर्ष की वर्धित अवधि 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध थी ।

विश्व बैंक ने भारत की वित्तीय वर्ष 14 के वृध्दि अनुमान को घटाकर 6.1 प्रतिशत किया

विश्व बैंक ने अपने अद्यतन भारत विकास अद्यतन में चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत के लिए अपने वृध्दि अनुमान 7.0 प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया है। अद्यतन में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वृध्दि गति को पुनः प्राप्त कर रही है और वृध्दि क्रमिक रूप से अपनी उच्च दीर्घावधि वृध्दि संभाव्यता को पुनः प्राप्त कर लेगी । यद्यपि चालू खाता घाटा वित्तीय वर्ष 2013 में रेकॉर्ड ऊँचाई पर था, मध्यम अवधि में इसके कम होने की संभावना है । विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि राजकोषीय घाटा कम हुआ है, राजकोषीय उत्पाद जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात को कम करने में महत्वपूर्ण है ।

पूंजी निर्गम के वितरण प्रकट करें : बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने तुलनपत्र में जारी किये गये सभी पूंजी लिखतों के विवरण प्रकट करें । बासेल-III बैंकिंग पूंजी सुधार के अनुरुप जारी किया गया नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा और उधारदाताओं को अपने सितंबर समाप्ति के तुलनपत्र में विवरण रिपोर्ट करना होगा । इससे विनियामक पूंजी की पारदर्शिता में सुधार आने और बाजार अनुशासन बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

एक्ज़िम बैंक को म्यांमार में कार्यालय खोलने के लिए बैंकिंग लाइसेंस मिला

एक्ज़िम बैंक को शुक्रवार 14 जून, 2013 को म्यांमार में यांगून में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए बैंकिंग लाइसेंस मिला है । श्री यू. थीन जॉ, उप महा निदेशक, वित्तीय संस्थान पर्यवेक्षण विभाग, सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार द्वारा श्री डेविड रस्कीना, कार्यपालक निदेशक, एक्ज़िम बैंक को लाईसेंस सौंपा गया । भारत और म्यांमार के बीच व्यापार संबंधों में हाल के वर्षो में अच्छी प्रवृत्ति देखी गई है । म्यांमार के साथ भारत का कुल व्यापार 2007-08 के 1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2012-13 में 1.9 बिलियन यूएस डॉलर पहुँच गया है जिसमें 4.1 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज हुई है ।

अप्रैल 2013 से लागू डीआईपीपी की एफडीआई नीति

एफडीआई अंतर्वाह को और सुगम बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 5 अप्रैल, 2013 से लागू एक समेलित एफडीआई नीति जारी की है । नीति में भारत में एफडीआई अंतर्वाह के संबंध में जारी तथा लागू सभी प्रेस नोट / प्रेस विज्ञप्तियां / स्पष्टीकरण / परिपत्र शामिल हैं ।

एक्ज़िम बैंक द्वारा 2012-13 में जबर्दस्त कारोबार वृध्दि दर्ज की गई

वित्तीय कार्य-निष्पादन

चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बावजूद एक्ज़िम बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012-13 में अच्छा कार्य परिणाम दर्ज किया है । बैंक का ऋण पोर्टफोलियो 20 प्रतिशत बढ़कर ₹ 65,563 करोड़ हो गया । निवल लाभ 10 प्रतिशत बढ़कर ₹ 742 करोड़ हो गया और बैंक की निवल संपत्ति 20 प्रतिशत बढ़कर ₹ 7,239 करोड़ हो गयी । बैंक केन्द्र सरकार को पूंजी पर प्रतिफल के रूप में ₹ 263 करोड़ अदा करेगा जो पिछले वित्तीय वर्ष से 28 प्रतिशत अधिक है । बैंक का कुल कारोबार 21 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,37,774 करोड़ हो गया ।

व्यवसाय कार्य-निष्पादन

वर्ष के दौरान कुल 833.59 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गईं । यथा मार्च 2013 को बैंक ने कुल 8.57 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण वचन-बध्दताओं के साथ 75 देशों को शामिल करते हुए 167 ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं ।

बैंक ने क्रेता ऋण-राष्ट्रीय निर्यात बीमा लेखा के अंतर्गत 291 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की परियोजनाओं के लिए कुल 248 मिलियन यूएस डॉलर की राशि मंजूर की है और 51 परियोजनाओं को कुल 5.14 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता देने के लिए सिध्दांत रूप में वचनबध्दता प्रदान की है ।

वर्ष 2012-13 में एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजना निर्यात संविदाएं ₹ 24,255 करोड़ की थीं जो 38 देशों में 57 कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई थीं । 49 कंपनियों को 20 देशो में उनके समुद्रपारीय निवेशों के वित्तपोषण के लिए कुल ₹ 4,228 करोड़ की समुद्रपारीय निवेश सहायता मंजूर की गई। एक्ज़िम बैंक ने अब तक 71 देशों में 352 कंपनियों द्वारा स्थापित 436 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है। समुद्रपारीय निवेश के लिए कुल सहायता ₹ 29, 280 करोड़ रही ।

संसाधन / ट्रेजरी

बैंक ने 2012-13 में कुल ₹ 38,571 करोड़ की उधार राशियां जुटाई जिनमें ₹ 17, 012 करोड़ के रुपया संसाधन और ₹ 21,559 करोड के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में नये बेंचमार्क

एक्ज़िम बैंक उभरते बाजार बांड सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय संस्था बन गया । बैंक ने ईएमबीआई समावेशन का लाभ उठाते हुए 5 वर्षीय 500 मिलियन यूएस डॉलर और 10 वर्षीय 750 मिलियन यूएस डॉलर के यूरोडॉलर बांड न्यूनतम दर पर जारी किये । यह 5 वर्षीय 200 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर निर्गम के साथ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बाजार में कदम रखने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई और 5 वर्षीय सिंगापुर डॉलर मूल्यांकित बांड (250 मिलियन एसजीडी) जारी करने वाली पहली भारतीय संस्था बन गई ।

एक्ज़िम बैंक ने 170 मिलियन यूएस डॉलर का दूसरा उरीदाशी बांड निर्गम जारी किया और उरीदाशी बाजार में स्वीकृत एकमात्र भारतीय संस्था बना हुआ है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने जलवायु परिवर्तनों को रोकने वाली परियोजनाओं को सहायता करने के लिए यूरोपीन निवेश बैंक से 150 मिलियन यूरो का 20 वर्षीय ऋण प्राप्त किया है ।

ग्रासरूट व्यवसाय पहलें

बैंक ने तंगेल तंतुजिबी उन्नयन संमबय समिति लि., बुनकर सहकारी समिति; ट्रस्ट-कला रक्षा - हस्त दस्तकारी वस्त्रों, सहायक सामग्री आदि का उत्पादन करने वाला; इंडस्ट्री क्रॉफ्ट्स प्राइवेट लि., हस्तशिल्प तथा हैंडलूम उत्पादों के उत्पादन में लगा एक संगठन; को उनकी निर्यात क्षमता में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की ।

बैंक ने नारियल शेल क्रॉफ्ट के लिए रचनात्मक तथा आधुनिक डिज़ाइन विकसित करने के लिए महिला शिल्पियों के लिए डिज़ाइन विकास तथा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया । बिदर बिदरी यूथ मंडल, एक स्वयं सहायता समूह के लिए डिज़ाइन विकास प्रशिक्षण चरण-II; सफल विपणन तथा निर्यात के लिए पैकेजिंग, अग्रेषण तथा वित्त; झारक्रॉफ्ट, झारखंड सरकार का एक उपक्रम के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग तथा पैकेजिंग पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं । बैंक ने विश्व क्रॉफ्ट परिषद की साझेदारी में हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्यरत छात्रों की सहायता के लिए एक्ज़िम बैंक - डब्ल्यूसीसी इंटरनेशनल क्राफ्ट फिल्म प्रतियोगिता का भी आयोजन किया ।

वर्ष के दौरान बैंक ने राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान के साथ एमओयू और ग्रामीण प्रौद्योगिकी एवं कारोबार उद्भवन, आईआईटी मद्रास में एक उद्भवन, (इन्क्युबेटर) कक्ष, के साथ एमओसी पर हस्ताक्षर किये ।

दक्षिण-दक्षिण सहयोग

एक्ज़िम बैंक ने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण कोरिया देशों के साथ दो बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग करारों अर्थात् अफ्रीका के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय इंफ्रास्ट्रक्चर सह-वित्तपोषण तथा सतत विकास के लिए ब्रिक्स बहुपक्षीय सहयोग तथा सह-वित्तपोषण करार पर हस्ताक्षर किये ।

बैंक ने सॉर्क विकास निधि (एसडीएफ) के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया और इसके परिचालन, दिशा, उत्पादों के पोर्टफोलियो की दृष्टि से और बहुपक्षीय हैसियत प्राप्त करने तथा इसके संसाधन आधार को विस्तारित करने की दीर्घकालिक योजना के रूप में एसडीएफ के लिए एक रणनीति तैयार की ।

ज्ञान का आदान-प्रदान

बैंक ने समसामयिक आलेख और कार्यकारी आलेख के रूप में वर्ष 2012-13 के दौरान 9 शोध-पत्र प्रकाशित किये । ये हैं : पश्चिम अफ्रिका : भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन; चीन के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की संभाव्यता : संक्षिप्त विश्लेषण; म्यांमार के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की संभाव्यता : संक्षिप्त विश्लेषण; पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की संभाव्यता : संक्षिप्त विश्लेषण; ईरान के साथ भारत के व्यापार को बढ़ाने की संभाव्यता : संक्षिप्त विश्लेषण; क्षेत्रीय सहयोग हेतु हिन्द महासागर रिम संघ : भारत की व्यापार तथा निवेश संभाव्यता का अध्ययन; भारतीय रसायन उद्योग: वैश्विक माँग का अन्वेषण; फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकीय खोज; सेवाओं का निर्यात तथा अपतटीय आउट सोर्सिंग ।

सर्जनात्मक उद्योग : अनुकरणीय समुत्थान-शक्ति का प्रदर्शन

सर्जनात्मक उद्योग का अर्थ बौध्दिक सम्पदा पर अत्यधिक निर्भरता के साथ प्रतीकात्मक उत्पाद के उत्पादन संबंधी आर्थिक कार्यकलाप है (अंकटाड 2004)। इस उद्योग में कार्यकलाप कौशल-गहन होते हैं तथा इसमें व्यापार और बौध्दिक संपदा अधिकार के माध्यम से आय के सृजन के लिए काफी गुंजाइश होती है। **(प्रदर्श)**

प्रदर्श : सर्जनात्मक उद्योग के संघटक

धरोहर	कला	माध्यम	प्रयोजनमूलक सृजन
पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां कला शिल्प त्यौहार उत्सव	**दृश्य कला** चित्रकारी धर्मग्रंथ पुरावशेष फोटोग्राफी	**प्रकाशन एवं मुद्रण माध्यम** पुस्तक समाचार-पत्र प्रेस तथा अन्य प्रकाशन	**डिज़ाइन** आंतरिक ग्राफिक फैशन आभूषण खिलौने
सांस्कृतिक साइट ऐतिहासिक पुरोलेख म्यूजियम लाइब्रेरी आर्चिव	**प्रदर्शन कला** संगीत थिएटर नृत्य ओपेरा कठपुतली सर्कस	**श्रव्य-दृश्य** फिल्म, टीवी व रेडियो प्रसारण **नये माध्यम** डिजिटाइज्ड सामग्री सॉफ्टवेयर विडियो कैमरा ऐनिमेशन	**सर्जनात्मक सेवाएं** आर्किटेक्चर विज्ञापन सर्जनात्मक आर एंड डी सांस्कृतिक सेवाएं डिजिटल सेवाएं

अंकटाड के अनुसार, सर्जनात्मक उद्योग के वैश्विक निर्यात का मूल्य 2003 के 338.0 बिलियन यूएस डॉलर से 7.8 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ते हुए 2011 में 614.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया । सर्जनात्मक माल का सर्जनात्मक उद्योग के वैश्विक व्यापार में अधिकांश हिस्सा है । हालांकि 2003-2011 के दौरान सर्जनात्मक माल के लिए सीएजीआर 6.9 प्रतिशत रहा, जबकि सर्जनात्मक सेवाओं के लिए यह 9.7 प्रतिशत रहा । सर्जनात्मक उद्योग के भीतर डिज़ाइन क्षेत्र का 2011 में 66.4 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा । यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि विकासशील देश निर्यात रैंकिंग में अब भी आगे हैं, सर्जनात्मक माल के निर्यात में विकासशील देशों का हिस्सा 2003 के 39.4 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 50.1 प्रतिशत हो गया है ।

सर्जनात्मक उद्योग के भारतीय निर्यात में 2003-2011 की अवधि के दौरान 26.8 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृध्दि दर्ज की गई है । भारत 2011 में सर्जनात्मक माल का छठा सबसे बड़ा निर्यातक था जो महत्वपूर्ण सुधार (2003 में 13 वाँ स्थान) दर्शाता है । सर्जनात्मक माल के भारतीय निर्यात समूह में कालीन, पेंटिंग, यार्न, उत्सव वस्तुएं, शीशे के बर्तन तथा कागज निर्मित वस्तुएं शामिल हैं । भारत में सर्जनात्मक माल क्षेत्र के भीतर निर्यात में डिज़ाइन खंड का योगदान सर्वाधिक (91.0 प्रतिशत) रहा । नये मीडिया खंड (रिकार्डिंग मीडिया तथा विडियो गेम्स) ने मुख्यतः रिकॉर्डिंग मीडिया की बदौलत गत वर्ष की तुलना में 2011 में 124.4 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की ।

सर्जनात्मक उद्योग के कुछ क्षेत्रों में, भारतीय सरकार अपनी वैश्विक समकक्षियों के साथ कदम-से-कदम मिला कर चल रही है । भारत में पहले से ही एक राष्ट्रीय डिज़ाइन नीति, 2007 है । डिज़ाइन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर भी जोर दिया गया है । इसके अलावा, डिज़ाइन के बारे में नीतिगत सिफारिश देने के उद्देश्य से भारतीय डिज़ाइन परिषद का गठन किया गया है । सरकार सक्रिय रही है और 2010 में एमएसएमई को डिज़ाइन विशेषज्ञता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के अंतर्गत डिज़ाइन क्लिनिक योजनाएं शुरू की हैं ।

तथापि, वृध्दि संभावनाओं के बीच, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है । बौध्दिक सम्पदा तथा कॉपीराइट अधिकार को प्रतिधित तथा सुरक्षित किये जाने की आवश्यकता है ताकि सर्जनात्मक उद्योग क्षेत्र वाणिज्यिक रूप से सफल बन सके । इस दिशा में, सरकार ने अधिनियम तथा कानून बनाये हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समतुल्य हैं । सरकार ने मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से निजता पर अभियान चलाने के लिए 12 वीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत एक योजना का भी अनुमोदन किया है ।

हालांकि भारत विश्व में सर्जनात्मक माल का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, तथापि इसका हिस्सा सिर्फ 4.9 प्रतिशत है । अतएव हिस्सा बढ़ाने के प्रयास किये जाने की आवश्यकता है । गतिशील सर्जनात्मक उद्योग विगत समय में अत्यधिक लचीलापन दर्शाया है ।

एक्ज़िम बैंक सर्जनात्मक उद्योगों के वित्तपोषण हेतु एडफिएप से विशेष 'प्लाक ऑफ मेरिट' से सम्मानित

भारतीय एक्ज़िम बैंक को उलानबतार, मंगोलिया में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सर्जनात्मक उद्योगों के वित्तपोषण हेतु कार्यक्रम के लिए एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में विकास वित्तीय संस्थाओं के संघ (एडफिएप) द्वारा विशेष 'प्लाक ऑक मेरिट' से सम्मानित किया गया ।

यह पुरस्कार निर्यातोन्मुख भारतीय सर्जनात्मक उद्योग की जरुरतों को पूरा करने के लिए तैयार किये गए उसके विशिष्ट वित्तपोषण कार्यक्रम के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया । वैयक्तिक उद्यमियों का वित्तपोषण करने के अलावा, एक्ज़िम बैंक ने सर्जनात्मक उद्योग के लिए सामान्य बुनियाबी सुविधाएं निर्मित करने और क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्य में सहायता प्रदान करने का भी प्रयास किया है । वित्तपोषण कार्यक्रम में इस क्षेत्र पर रणनीतिक ध्यान देना शामिल है जिसमें एमएसएमई को प्रधानता है और न केवल निर्यात बढ़ाने, बल्कि निर्यात पात्रता बढ़ाने और भारतीय सर्जनात्मकता उद्योग की अभिमुख्यता पर भी जोर देता है ।

होम टेक्सटाइल घरों के लिए आराम, संरक्षण, सजावट तथा फैशन प्रदान करने में शताब्दियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है । होम टेक्सटाइल में गद्दे, पलंगपोश, कम्बल, परदे, फर्श कवरिंग, डिश लिनिन, मेजपोश, टॉयलेट तथा किचन लिनिन और टेक्सटाइल फर्नीशिंग शामिल हैं । होम टेक्सटाइल के लिए बाजार अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल बाजार की एमएफए व्यवस्था के बाद बढ़ा है । बढ़ती प्रयोज्य आय और रियल एस्टेट में तेजी ने भी देशी माँग को बढ़ावा दिया है । ऐसी सकारात्मक वैश्विक तथा देशी माँग के फलस्वरुप भारत में होम टेक्सटाइल उद्योग के कुछ बड़े उत्पादक हैं, जैसे वेलस्पून जो विश्व में सबसे बड़ा होम टेक्सटाइल उत्पादक है और विश्व में टेरी टॉवल के चार शीर्ष उत्पादकों में है ।

व्यापार मोर्चे पर उत्कृष्टता

2012 के दौरान भारत चीन (18.2 बिलियन यूएस डॉलर 39.1 प्रतिशत हिस्सा) के बाद विश्व में होम टेक्सटाइल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका हिस्सा 4.4 बिलियन यूएस डॉलर था और विश्व निर्यात में 9.4 प्रतिशत हिस्सा था ।

होम टेक्सटाइल के निर्यात में 2011 में जबर्दस्त उछाल आया, यह उछाल विशेषकर दो उत्पाद खंडों की बदौलत आया - कम्बल तथा यात्रा कम्बल (रॅग) (एच एस कोड - 6301) और बेड, मेज, टॉयलेट तथा किचन लिनिन (एस एस कोड - 6302) । इन दो खंडों ने 2011 में क्रमशः 61.1 प्रतिशत और 55.5 प्रतिशत की वृध्दि दर्ज की । कम्बल तथा ट्रैवलिंग रग्स (एच एस कोड - 6301) तथा अन्य फर्नीशिंग वस्तुओं (एच एस कोड - 6304) के आयात ने भी 2011 में क्रमशः 66.2 प्रतिशत तथा 65.9 प्रतिशत की उच्च वृध्दि दर प्रदर्शित की । इसके बाद 2012 में इन दो खंडों का प्रदर्शन सामान्य रहा । 2012 में निर्यात कम होकर 4.0 प्रतिशत रहा, जबकि होम टेक्सटाइल के आयात में गत वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की गिरावट आयी **(तालिका)** ।

भारत के होम टेक्सटाइल का प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान यूएसए था जिसका कुल निर्यात में 52.1 प्रतिशत हिस्सा रहा; इसके बाद जर्मनी (7.3 प्रतिशत), यूके (6.8 प्रतिशत), आस्ट्रेलिया (2.7 प्रतिशत), यूएई (2.6 प्रतिशत), कनाडा (2.3 प्रतिशत), तथा फ्रांस (2.2 प्रतिशत) का स्थान रहा । प्रमुख स्त्रोत देश हैं - चीन (62.3 प्रतिशत), यूएसए (7.5 प्रतिशत), थाईलैंड (0.1 प्रतिशत), यूएई (3.4 प्रतिशत), बेल्जियम (3.1 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (1.8 प्रतिशत) ।

भावी संभावनाएं

उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, होम टेक्सटाइल तथा फर्नीशिंग बाजार 2015 तक ₹ 26,600 करोड़ तक पहुँच जाने का अनुमान है । इस बाजार के लिए कुछ मुख्य संवाहक हैं : घरानों की संख्या तथा विवेकाधीन आय में वृध्दि और अंतिम-उपभोग क्षेत्रों जैसे आवास, कार्यालय अतिथ्य तथा स्वास्थ्य-देखभाल में वृद्धि । इस बाजार में असंगठित क्षेत्र की प्रधानता है । 10 प्रतिशत से कम बाजार संगठित है और इस प्रकार संगठित क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए बढ़ने के लिए विपुल अवसर हैं । संपूर्ण भारत में उपस्थिति वाले कुछ प्रमुख ब्रांड हैं: बाम्बे डाइंग, स्पेसेज़, फैबइंडिया, पोर्टिको, मैस्पर तथा ऐटमॉस्फियर । कई बड़े आकार के रिटेलरों जैसे शॉपर्स स्टॉप, बिग बाजार, होम टाउन, होम सेंटर, रिलायंस मार्ट तथा वेस्टसाइड के पास भी होम फर्नीशिंग विभाग हैं। होम टेक्सटाइल के भीतर विभिन्न खंडों में से बेड लिनिन तथा बाथ लिनिन कुल बाजार आकार में दो-तिहाई योगदान देते हैं । किचन लिनिन, परदे, कमरे के साज-सामान तथा गलीचा / कालीन बाजार में शेष योगदान देते हैं ।

होम टेक्सटाइल उद्योग अपनी फैब्रिक आवश्यकता के लिए पॉवरलूम क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है । पिछले कुछ वर्षों में पॉवरलूम क्षेत्र की प्रौद्योगिकी में काफी उन्नयन हुआ है जिससे होम टेक्सटाइल उद्योग की वृध्दि में सहायता मिली है । व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत पावरलूम बृहत् क्लस्टर भी विकसित किये गए जिनसे उद्योग के भीतर लघु एवं मध्यम उद्यमों को फायदा पहुँचेगा ।

वर्ष 2001 में राष्ट्रीय टेक्सटाइल डिज़ाइन केन्द्र की भी स्थापना की गई जो देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए डिज़ाइन प्रवृत्ति कलर पूर्वानुमान प्रदान करता हैं । फर्नीशिंग के लिए, कुल 454 डिज़ाइनें निःशुल्क पहुँच के लिए उपलब्ध हैं । इसके अलावा, हैंडलूम निर्यात संवर्धन परिषद् हैंडलूम उत्पादों के संवर्धन में सहायता करती है जो व्यापार तथा मार्केटिंग के लिए निर्यातकों तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को सहायता प्रदान करती है । वस्त्र मंत्रालय होम टेक्सटाइल उद्योग के बारे में कार्यशालाएं तथा सेमिनार भी नियमित रूप से आयोजित करता हैं। फलते-फूलते बाजार तथा सरकारी पहलों के फलस्वरुप भारतीय होम टेक्सटाइल उद्योग का भविष्य उज्ज्वल दिखाई देता हैं ।

तालिका : भारत होम टेक्सटाइल निर्यात तथा आयात, 2012 **(मिलियन यूएस डॉलर)**

एच एस कोड	वस्तु	निर्यात	वर्ष दर वर्ष वृध्दि 2011	वर्ष दर वर्ष वृध्दि 2012	% हिस्सा 2012	आयात	वर्ष दर वर्ष वृध्दि 2011	वर्ष दर वर्ष वृध्दि 2012	% हिस्सा 2012
6301	कम्बल तथा ट्रैवलिंग रग्स	122.7	61.1	2.0	2.8	47.8	66.2	-20.1	26.6
6302	बेड, टेबल, टॉयलेट तथा किचन लिनिन	1324.1	55.5	-8.3	30.4	3.5	6.0	16.6	2.0
6303	परदे ड्रेप सहित तथा आंतरिक ब्लाइंड्स, परदा या पलंग परदा	147.5	19.8	-15.0	3.4	5.4	18.3	1.6	3.0
6304	अन्य फर्नीशिंग वस्तुएं, शीर्षक 9404 की वस्तुओं को छोड़कर	1409.3	5.0	20.6	32.4	50.9	65.9	-17.8	28.4
57	गलीचा तथा अन्य टेक्सटाइल फर्श आवरण	1350.7	-3.8	5.6	31.0	71.8	25.7	-14.0	40.0
कुल		**4354.2**	**16.6**	**4.0**	**100.0**	**179.5**	**45.2**	**-16.0**	**100**

स्त्रोत : ट्रेडमैप

12 अर्जेंटीना में निवेश अवसर

अर्जेंटीना पिछले दस वर्षों में विश्व में तेजी से बढ़ते देशों में शामिल हो गया है. वर्तमान वृद्धि मॉडल ईक्विटी तथा सामाजिक समावेशन के साथ सतत् विकास को प्राथमिकता देता है । अर्जेंटीना पिछले चार वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक के वार्षिक औसत के साथ परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में एफडीआई के नये रेकॉड लाभ पर पहुंच गया है, देश में पिछले 30 वर्षों में निवेश की उच्चतर दर (2011 में जीडीपी वे 24.5 प्रतिशत के समतुल्य) रही है जो बहुविध निवेश अवसरों की विविधता और लाभप्रदता द्वारा संचालित रही है ।

अर्जेंटीना बहुविध क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निवेश अवसर प्रदान करता है । इसके प्राकृतिक संसाधन, अत्यंत कुशल कामगार और प्रौद्योगिकीय एवं औद्योगिक विकास की इसकी परंपरा इसके मजबूत पहलू हैं जो देश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य स्थान बनाता है। अर्जेंटीना में विभिन्न प्रकार के उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रों में खाद्य एवं पेय, जैव-प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, सॉफ्टवेअर एवं आईटी सेवाएं, सर्जनात्मक उद्योग, मोटर एवं मोटर पुर्जे, तकनीकी तथा व्यावसायिक सेवाएं और पूंजीगत माल शामिल हैं ।

देश खाद्य एवं पेय के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है । इसका निर्यात 25 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक है और इस सेक्टर को उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण मानक प्राप्त है ।

जैव प्रौद्योगिकी में अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका से आगे है जो कृषि, मानव तथा पशु स्वास्थ्य में अपने वैज्ञानिक एवं नवोन्मेषी संभाव्यता के लिए विख्यात है । बढ़ते सार्वजनिक तथा निजी प्रयासों का समूहन और मजबूज औद्योगिक परंपरा तथा गुणवत्ता इस क्षेत्र को गतिशीलता प्रदान करती है ।

देश के पास नवीकरणीय ऊर्जा में भी विपुल संभाव्यता है । अर्जेंटीना बायो-डीजल का सबसे बड़ा निर्यातक तथा सबसे बड़ा उत्पादक है और अन्य के साथ-साथ एथनॉल, पवन, सौर तथा हाइड्रोपॉवर में आगे बढ़ने के लिए संसाधन तथा क्षमताएं हैं ।

शराब उद्योग प्रमाणिक सफलता वाला क्षेत्र है । अर्जेंटीना शराब का विश्व में पाँचवां सबसे बड़ा उत्पादक और दसवां सबसे बड़ा निर्यातक है । चिरकालिक राष्ट्रीय उद्योग देश में शराब क्षेत्र के तीव्र विस्तार को समर्थन देता है ।

इस देश में मोटर तथा मोटर पुरज़ा उद्योग का लम्बा इतिहास है । मोटर उत्पादन दक्षिण अमेरिका में मात्रा की दृष्टि से दूसरा है ।

सेवा क्षेत्र के मोर्चे पर, अर्जेंटीना में सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवा क्षेत्र में लघु एवं मझौले अत्यधिक नवोन्मेषी उद्यमों के बढ़ते तथा सक्रिय नेटवर्क के साथ 3,800 बहुराष्ट्रीय फर्मों का नेटवर्क है ।

सर्जनात्मक उद्योगों में, अर्जेंटीना मूल टीवी प्ररूपों का लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा निर्यातक और विश्व में चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है । देश को प्रतिस्पर्धी लागत पर गुणवत्तापूर्ण माल पेश करते हुए और उच्च वृद्धि संभाव्यता के साथ कई खंडों में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल है ।

उपर्युक्त के अलावा, देश आउटसोर्सिंग तथा पूंजीगत माल उद्योगों में निवेश संभावनाएं प्रस्तुत करता है ।

निवेश का विकास तथा व्यापार संवर्धन

अर्जेंटीना का विदेश मंत्रालय वर्तमान में उत्पादक निवेश और कार्य गुणवत्ता आकर्षित करने पर कार्य कर रहा है। इन प्रयासों को विदेश मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विभाग के अंतर्गत निवेश विकास तथा व्यापार संवर्धन हेतु अवर-सचिवालय के माध्यम से सारणीबद्ध किया जा रहा है ।

निवेशकों के लिए उपलब्ध साधन

निवेश विकास तथा व्यापार संवर्धन हेतु अवर-सचिवालय के पास विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं ।

बैंक ऑफ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स (बीएपीआईपी) अर्जेंटीना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सृजित साधनों में से एक है । इसमें ऑनलाइन निवेश परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो शामिल है जिसका मुख्य उद्देश्य अर्जेंटीना में उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों के साथ विश्व भर में लिंक संभाव्य निवेशकों की सहायता करना है ।

बीएपीआईपी की वेबसाइट स्पैनिश तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूरे देश में निवेश परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है । यह वेबसाइट एक वेब पोर्टल भी प्रस्तुत करती है । जो संभाव्य निवेशकों को परियोजना मालिकों से जोड़ती है । राष्ट्रीय मंत्रालयों, प्रांतीय तथा नगरपालिका सरकारों और कारोबारी समुदायों के समन्वयन में निवेश विकास तथा व्यापार संवर्धन हेतु अवर-सचिवालय द्वारा इन परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जाता है । इसके अलावा, अवर सचिव सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं के निरूपण में तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं ।

निवेश संवर्धन के क्षेत्र में सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया गया एक अन्य साधन निवेशक सहायता के लिए क्षेत्र (http://inversiones.gov.ar/es/servicios-al-inversor या info@inversiones.gov.ar) है जो अर्जेंटीना में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को वैयक्तिक परामर्श तथा सहायता प्रदान करता है । इसमें परियोजना के सभी चरण अर्थात् कंपनी के मूल्यांकन से लेकर उसके कमीशनिंग, परिचालन या विस्तार तक के सभी चरण शामिल होते हैं । इसके अलावा, निवेशक सहायता के लिए क्षेत्र विदेशी निवेशकों और स्थानीय कारोबार के बीच भागीदारी स्थापित करने में सहायता प्रदान कराता है ।

अंत में, कानूनी ढांचे, प्रोत्साहन योजनाएं, कर प्रणाली तथा अर्जेंटीना में निवेश की स्थापना के लिए आवश्यक अन्य आंकड़ों पर जानकारी के साथ अर्जेंटीना में विदेशी निवेश पर एक निवेशक गाईड (http://www.inversiones.gov.ar) उपलब्ध है ।

विपणन सलाहकारी सेवाएं

अप्रैल-जून 2013

भारतीय निर्यात-आयात बैंक संवर्धनात्मक भूमिका निभाता है और अपनी विपणन सलाहकारी सेवा के माध्यम से भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता सृजित करने और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करता है। बैंक भारतीय फर्मों के उत्पादों तथा सेवाओं के लिए विदेशी वितरकों /खरीदारों/भागीदारों की पहचान करते हुए उनके अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रयासों में उनकी मदद करता है, बैंक भारतीय कंपनियों को सफलता शुल्क आधार पर उनकी समुद्रपारीय विपणन पहलों में सहायता करने के लिए अपनी उच्च अंतर्राष्ट्रीय साख, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गहन जानकारी और समझ तथा सुस्थापित संस्थागत संबद्धताओं और साथ ही विदेशों में अपनी भौतिक उपस्थिति का भरपूर इस्तेमाल करता है।

बैंक ने इस विशिष्ट कार्यक्रम की सक्रिय मार्केटिंग की और प्रमुख उत्पादों के लिए विदेशी तथा देशी बाजारों की पहचान करने, उनके लिए ऑर्डर उत्पन्न करने में योगदान दिया है। चिकित्सा, हस्तशिल्प तथा हैंडलूम, कृषि तथा खाद्य एवं पेय, इंजिनियरिंग, टेक्सटाईल, औषधि एवं सौन्दर्य प्रसाधन, पुष्पकृषि क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई. बैंक पुराने रिश्तों को फिर से ताज़ा करने और आयातक तथा निर्यातक के बीच सहबद्धताओं को फिर से स्थापित करने में भी सहायता करता है।

बैंक ने मुंबई आधारित ताजा फलों के एक निर्यातक की सिंगापुर आधारित आयातक के साथ उसके पुराने रिश्तों को फिर से तरोताज़ा करने में सहायता की. निर्यातक ने पहले सिंगापुर आधारित कंपनी के साथ एक सौदा किया था. किंतु अगले दो वर्ष तक कोई ऑर्डर नहीं मिला। बैंक ने सिंगापुर आधारित कंपनी से संपर्क किया और नई मार्केटिंग रणनीति के साथ उत्पाद को फिर से पेश किया। एक्ज़िम बैंक के समुद्रपारीय कार्यालय की सहायता एवं संपर्कों से तथा निरंतर सक्रिय फॉलो-अप से निर्यातक ने छः महीने की अवधि में 10 से अधिक ऑर्डरों को पूरा किया. इस प्रकार, एक्ज़िम बैंक ने संपर्कों को पुनः स्थापित करने तथा अतिरिक्त निर्यात को सुगम बनाने में सहायता की। निर्यात में विभिन्न प्रकार के ताजा फल तथा सब्जियां शामिल थीं। ग्रामीण घरानों को रोजगार प्रदान करने वाले और हस्तशिल्प एवं हैंडमूल के निर्माता भारत सरकार के एक अन्य उपक्रम को एक्ज़िम बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई। उत्पाद और उपक्रम की मौजूदा मार्केटिंग रणनीति की समीक्षा करने के बाद गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग तथा ब्रांड निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। एक्ज़िम बैंक ने जापान जैसे चुनिंदा बाजारों के लिए उत्पाद विकास हेतु डिज़ाइन की खोज में भी सहायता की। एक्ज़िम बैंक ने उपर्युक्त आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को मन में बिठाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया ताकि उत्पाद को व्यापक स्वीकृति मिल सके। लगभग 250 शिल्पकारों ने कार्यशाला में भाग लिया और उन्हें ग्राफिक्स के महत्व, पैकेजिंग सामग्री एवं प्रक्रिया, मूल्य योजन तथा ग्राहक पसन्द के बारे में जानकारी दी गई। इसमें आपूर्ति श्रृंखला वितरण के लिए बार कोडिंग, लेबल लगाना तथा परिवहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का मूल्यांकन जैसे विषय भी शामिल किये गये।

कार्यशाला पूरी होने के बाद भारत में दो प्रमुख खुदरा वस्त्र श्रृंखलाओं को उत्पाद पेश किये गये। एक्ज़िम बैंक की सहायता से उत्पाद सफलतापूर्वक पेश किये गये और ग्राहकों का बहु वांछित ध्यान आकृष्ट किया गया। इससे उपक्रम को ब्रांड निर्माण तथा ग्रामिणों एवं आदिवासियों को रोजगार प्रदान करने में सहायता मिली।

बैंक अब उपक्रम को उच्च स्तर पर लाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने में उनकी सहायता करने में भी लगा है।

कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें :

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
मुंबई
फोन : (022)22172713
ईमेल : deepali@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

'बियांड फैक्टरी एशिया : फ्यूइलिंग ग्रोथ इन ए चैलेजिंग वर्ल्ड' - एशियाई विकास बैंक

विगत कई दशकों में एशियाई क्षेत्र ने व्यापक अंतर-क्षेत्रीय विविधता के बावजूद जबर्दस्त गतिशीलता दिखाई है। कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में निर्यात आधारित विनिर्माण में सफलता ने प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को विकसित देशों के स्तर पर पहुंचायी। औद्योगिकीकरण और गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या के पलायन ने क्षेत्र के कई देशों में निरंतर मजबूत आर्थिक वृद्धि प्रदान की। एशियाई विकास बैंक द्वारा हालिया प्रकाशन में इस बात की जांच की गई है कि विकासशील एशिया को कौशल तथा प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए और निजी क्षेत्र को सस्ते विनिर्माण से आगे निकलना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी रहे।

प्रकाशन में प्रयुक्त फैक्टरी इंडिया शब्द से विभिन्न एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में उन पुरजों तथा सहायक उपकरणों को उत्पादन करने वाली फैक्टरियों को जोड़ने वाले क्षेत्रीय उत्पादन नेटवर्कों के मॉडल से संबंधित है जिन्हें उसके बाद असेम्बल किया जाता है और अंतिम उत्पाद मुख्यतः उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को प्रेषित किया जाता है।

प्रकाशन ने इस बात को रेखांकित किया है कि एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण में सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अमेरिका, यूरोप तथा जापान में धीमी वृद्धि दर के साथ बढ़ते एशियाई मध्य वर्ग का अर्थ यह है कि मांग विकसित बाजारों से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर शिफ्ट कर रही है।

प्रकाशन में यह भी सुझाव दिया गया है कि निजी क्षेत्र को मूल्य श्रृंखला की ओर बढ़ने में सहायता करने और निधियां जुटाने तथा जोखिम का प्रबंध करने के लिए कंपनियों के लिए आवश्यक वित्तीय बाजार विकसित करने के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी. इस बीच, देशों को ऐसे कौशल सीखने में अपने लोगों की मदद करनी चाहिए जो कपंनियों को अधिक परिष्कृत माल का उत्पादन करने के लिए आवश्यक होता है और ऐसे अनुसंधान में निवेश करना चाहिए जो नई प्रौद्योगिकियों के विकास तथा अंगीकरण को प्रोत्साहित करें।

14 देशों का सूक्ष्मावलोकन

नाइजीरिया

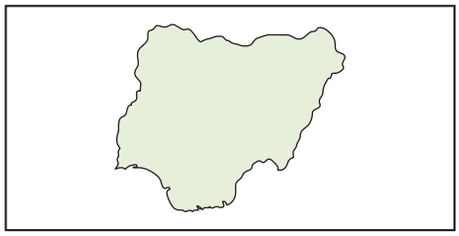

नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है जो लगभग 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का निर्यात करता है। यह उसके कुल पण्य निर्यात का 85 प्रतिशत है और उसके राजकोषीय राजस्व के 60-70 प्रतिशत के बीच है. तेल निर्यात पर उच्च निर्भरता देश को तेल की वैश्विक कीमतों में अस्थिरता के जोखिम में रखता है। इसके अलावा, आर्थिक नीति निर्माण में मुख्यतः समेकित बजट तथा लोक वित्त प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार, सीमित राजनीतिक इच्छाशक्ति और संरचनात्मक सुधार निष्पादित करने की क्षमता कमजोर आर्थिक स्थिति से जोखिमों को तीव्र करती है। देश के उत्तरी हिस्से में बढ़ते उपद्रव की घटनाओं का राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा व्यय पर असर पड़ने की संभावना है।

दक्षिण अफ्रीका

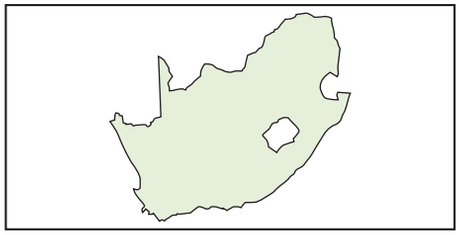

दक्षिण अफ्रीका उप सहारीय अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा अत्यधिक विविधीकृत अर्थव्यवस्था है। दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक वृद्धि के पीछे मुख्य संवाहक निजी उपभोग है। उपभोक्ता व्यय में नरमी, कमजोर जॉब परिप्रेक्ष्य, विश्वास के न्यून स्तर और ऋण के उच्च स्तर ने जीडीपी पर रोक लगा दिया है जो 2011 के 3.5 प्रतिशत की तुलना में 2012 में घटकर 2.5 प्रतिशत रहा। 2012 की दूसरी छमाही में विश्वास में गिरावट सामाजिक ऊथल-पुथल से संबंधित है जो इस अवधि के दौरान पूरे देश में व्याप्त रही। कोयला उद्योग में हालिया हड़ताल यह सूचित करती है कि सामाजिक अशांति 2013 में जारी रह सकती है। यद्यपि दक्षिण अफ्रीका उप सहारीय में सबसे आकर्षक कारोबारी माहौल प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था संरचनात्मक समस्याओं से जूझ रही है जो वृद्धि को उप-इष्टतम स्तर तक सीमित रख सकते हैं।

ईरान

राजकोषीय तथा बाह्य दोनों संतुलनों में तेल एवं गैस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ईरान में सरकारी निवेश तेल एवं गैस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्त जुटाने का प्रयास प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित होगा। अर्थव्यवस्था के खराब प्रबंध के साथ प्रतिबंधों के चलते उत्पादन में संकुचन, रियाल का तीव्र मूल्यहास और मुद्रास्फीति में तेजी आयी है। ईरान की राजकोषीय स्थिति तेल आय पर अत्यधिक निर्भर है और राजकोषीय वर्ष 2012-13 में निर्यात मात्रा में तीव्र गिरावट ने लोक वित्त के पर्याप्त रूप से बिगड़ने में योगदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, ईरान के तेल निर्यात में प्रतिबंधों के कारण 2012 में आधे की कटौती की गई जो 2012 के प्रारंभ में 2.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर वर्ष के अंत तक 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। साथ ही, प्रभावी मौद्रिक नीतियां लागू करने की केन्द्रीय बैंक की क्षमता प्रतिबंधों द्वारा नियंत्रित बनी रहेगी।

चीन

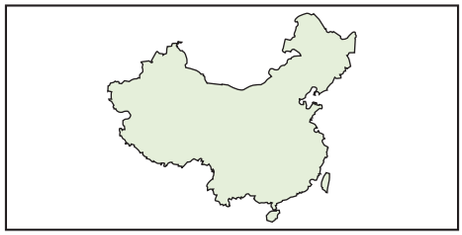

चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2011 से घट रही है जो 2011 में 9.3 प्रतिशत और 2012 में 7.8 प्रतिशत रही। 2013 की पहली छमाही में जीडीपी में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कमजोर स्फीतिकारी दबाव और आर्थिक वृद्धि की संभावना पर अनिश्चितता ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना को 2011 के उत्तरार्द्ध से निभावकारी मौद्रिक दृष्टिकोण बनाये रखने के लिए अनुकूल किया है। तथापि, ऋण वृद्धि में हालिया तेजी से सम्बध्द वित्तीय जोखिमों पर चिंता बनी हुई है। विगत कुछ वर्षों में अत्यंत तीव्र ऋण वृद्धि के चलते चीनी अर्थव्यवस्था में ऋण की कुल मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। इतना ही नहीं, बैंकों ने भी तुलन-पत्र से इतर पूंजी उत्पादों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। 2013 में केन्द्रीय बैंक द्वारा निभावकारी नीति दृष्टिकोण से हटने की संभावना है क्योंकि स्फीतिकारी चिंताएं पुनः उबर रही हैं। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार जून 2013 के अंत में 3500 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया जो विश्व में सर्वाधिक है। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में चीन मूल्य अंतरों के लिए अनुमति देने के बाद 2016 के आस-पास विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं।

रूस

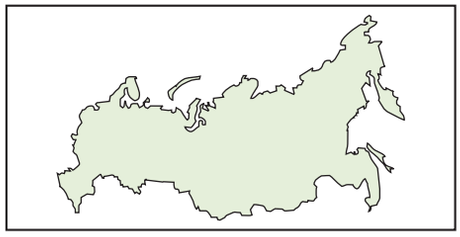

रूस के जीडीपी में 2011 के 4.3 प्रतिशत की तुलना में 2012 में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह स्थिति यूरो-क्षेत्र संकट के गहराने से उत्पन्न हुई है जिससे रूस के मुख्य निर्यात भागीदार प्रभावित हुए हैं। सांकेतिक जीडीपी 2012 के दौरान 2021 बिलियन यूएस डॉलर रहा जो रूस को विश्व में अठ्ठारहवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पर रखता है। देश के पास 486 बिलियन यूएस डॉलर का विपुल विदेशी मुद्रा भंडार है और 2012 में जीडीपी का 26 प्रतिशत बाह्य ऋण भार रहा है। पूंजी बहिर्वाह में गिरावट आयी जिससे सेंट्रल बैंक ऑफ रूस को अपने मुद्रा भंडार में और वृद्धि करनी पड़ी। अर्थव्यवस्था में तेल एवं गैस क्षेत्र की प्रधानता है जिसका कुल निर्यात में 70 प्रतिशत और जीडीपी में 28 प्रतिशत योगदान रहा। इससे सरकारी राजस्व तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है।

यूएस डॉलर

यूएस डॉलर संयुक्त राज्य की सरकारी मुद्रा है । संयुक्त राज्य से बाहर भी रिज़र्व मुद्रा के रूप में इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और यह फेडरल रिज़र्व बैंकिंग प्रणाली द्वारा नियंत्रित है ।

यूएस डॉलर 19 जून, 2013 को आयोजित फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएसी) की अपेक्षा से कम शांतिवाद बैठक के फलस्वरुप काफी मजबूत हुआ है । यूएस डॉलर को अमेरिका दरों में पुनः वृध्दि से लाभ हो रहा है जो 2013 में नई ऊंचाई पर पहुंच गयी हैं और 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बांड का प्रतिलाभ पिछले वर्ष के मध्य मार्च से अपने उच्चतम स्तर तक बढ़ गया है । दो महीने से कम समय में, 10 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बांड का प्रतिलाभ लगभग 76 आधार बिन्दु तेजी से बढ़ा है । अमेरिकी दरों में तीव्र वृध्दि प्रतिफल संवाहक व्यापारों (कैरी ट्रेड) के परिसमापन की ओर ले जा रही है जिससे अधिक आय वाली तथा उबरती बाजार मुद्राएं, विशेषकर उन्नत चालू खाता घाटे वाली मुद्राएं तेजी से कमजोर हो रही हैं ।

दक्षिण अफ्रीकी रैंड, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, ब्राजीलियाई रियाल तथा भारतीय रुपये सभी में पिछले दो महीने के दौरान यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आयी है । फेड द्वारा निवेशकों को इस बात से पुनः आश्वस्त करने में विफल होने पर प्रतिफल संवाहक व्यापारों का परिसमापन और बढ़ गया कि क्यूई की टेपरिंग और अंततः मौद्रिक कड़ाई सिर्फ क्रमिक होगी । अब फेड का अभिमत है कि आर्थिक संभावनाओं और श्रम बाजार में गिरावट का जोखिम इस गिरावट के बाद कम हुआ है ।

बाजार को उम्मीद है कि भारतीय रुपये सहित सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले यूएस डॉलर के और मजबूत होने की संभावना है । यूएस डॉलर की दर 30 जून, 2013 को 1 यूरो = 1.3010 यूएस डॉलर ; 1 जीबीपी = 1.5210 यूएस डॉलर ; 1 यूएस डॉलर = 99.1850 जापानी येन ; तथा 1 यूएस डॉलर = 59.5260 भारतीय रुपये उध्दृत हो रही थी ।

यूरो

यूरो (ईयूआर) यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित है । स्वतंत्र केन्द्रीय बैंक के रूप में ईसीबी यूरो की क्रय शक्ति और इस प्रकार यूरो क्षेत्र में मूल्य स्थिरता को बनाये रखने के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है ।

कई मूल देशों के विपरीत, ईसीबी किसी प्रकार की सॉवरिन ऋण पुरर्संरचना और री-प्रोफाइलिंग के विरुध्द है क्योंकि उसे डर है कि इससे बैंकिंग क्षेत्र में अतिरिक्त समस्याएं उत्पन्न होंगी । इसके लिए ईसीबी के मानकेतर उपायों को व्यापक बनाने की जरुरत पड़ सकती है । तथापि, ऋण की किसी री-प्रोफाइलिंग के बिना भी बाजार को उम्मीद है कि ईसीबी परिधि - देशी बैंकों की तंग स्थिति के कारण इस समय अपने मानकेतर उपायों को लागू रखेगा ।

चूंकि परिधिक देश अपने घर को व्यवस्थित करने की समस्या से जूझ रहे हैं, यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) आगामी महिनों में अधिक मानकेतर उपायों को कार्यान्वित करने के अधिक दबाव में आ सकता है और बाजार की अपेक्षा है कि हम नकारात्मक ब्याज दर नीति (एनआईआरपी) के समर्थन में केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों की बढ़ती संख्या देख सकते हैं क्योंकि क्षेत्र वृध्दि की राह पर लौटने के लिए संघर्षरत है ।

चूंकि वास्तविक अर्थव्यवस्था में विद्यमान कमजोरी मूल्य स्थिरता की आशंका पैदा करती है, ईसीबी के अध्यक्ष मैरियो ड्रैघी ने वर्ष की दूसरी छमाही में अधिक शांतिवाद की चेतावनी दी ।

यद्यपि, यूरो - यूएसडी एक आरोही चैनल के भीतर खरीदे-बेचे जाते हैं, यह जोड़ा निकट भविष्य में करेक्शन की ओर अग्रसर दिखाई देता है क्योंकि सापेक्ष शक्ति सूचकांक बिक्री से अधिक क्रय क्षेत्र से आता है । यूरो 30 जून 2013 को 1 यूरो = 1.3010 यूएस डॉलर की दर पर उध्दृत हो रहा था ।

येन

येन जापान की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा है और यह जेपीवाई के रूप में निर्दिष्ट है । अप्रैल 1949 में येन की दर 1 यूएस डॉलर = 360 जेपीवाई नियत की गई थी जिस दर पर वह 1971 तक बना रहा । ब्रेटॉन वुड्स प्रणाली के समाप्त हो जाने के बाद जापानी मौद्रिक प्रणाली अस्थिर विनिमय दर व्यवस्था में चली गयी ।

बैंक ऑफ जापान ने अपनी जनवरी बैठक में अपने 1.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति 'ध्येय' को अधिक औपचारिक 2.0 प्रतिशत मुद्रास्फीति 'लक्ष्य' से प्रतिस्थापित करने के बाद मार्च की अपनी बैठक में अपरिवर्तित मौद्रिक दृष्टिकोण बनाये रखा । जनवरी में इसने इस वर्ष के अंत में आस्ति क्रय कार्यक्रम के 101 ट्रिलियन जापानी येन के स्तर पहुंच जाने के बाद 2014 में असीमित अवधि के क्यूई प्रोग्राम दृष्टिकोण अपनाने का भी वचनबध्दता दी ।

येन मई में डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ और यूएस डॉलर के मुकाबले 103.73 जेपीवाई के निम्न स्तर पर पहुंच गया क्योंकि बाजार सहभागियों ने बैंक ऑफ जापान द्वारा आक्रामक मौद्रिक नरमी के लिए पोजिशन लेना जारी रखा । गवर्नर हरुहीको कुरोडा, जिन्होंने मार्च में मसाकी शिरकावा से कार्यभार ग्रहण किया, ने अपने पहले प्रेस सम्मेलन में इस बात को पुनः दोहराया कि वे दो वर्षों के भीतर 2.0 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हैं । तथापि, गवर्नर कुरोडा यह कहते हुए सतर्क भी थे कि बैंक ऑफ जापान अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कमजोर येन पर निर्भर नहीं करेगा । बैंक ऑफ जापान की नीति में ऐसे बदलाव, जो मुद्रास्फीति को उठा सके और देशी निवेशकों के लिए वार्षिक प्रतिलाभ को कम कर सके, पर विशेष फोकस से जापान से पूंजी का भारी मात्रा में निर्गमन अभी तक नहीं हुआ है ।

येन पिछले वर्ष में 21.1 प्रतिशत कमजोर हुआ है जो ब्लूमबर्ग सहसम्बध्दता भारित सूचकांक द्वारा नज़र रखी जाने वाली 10 विकसित बाजार मुद्राओं में सर्वाधिक है। जेपीवाई 30 जून, 2013 को 1 यूएस डॉलर = 99.1850 जेपीवाई पर उध्दृत हो रहा था ।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 : वार्षिक अनुपूरक 2013-14 की प्रमुख विशेषताएं

अप्रैल 2013 में घोषित विदेश व्यापार नीति 2009-14 के वार्षिक अनुपूरक 2013-14 ने विशेषकर रोजगार गहन क्षेत्रों में विदेश व्यापार कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला लागू की है ।

वार्षिक अनुपूरक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

➢ संवर्धनात्मक उपाय

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना को फिर से नया रूप देना

• सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों को लागू शून्य शुल्क ईपीसीजी तथा सभी क्षेत्रों पर 3 प्रतिशत शुल्क ईपीसीजी से सभी क्षेत्रों के लिए शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के रूप में सुसंगत बनाया ।

• होटलों, ट्रैवल एजेंटों या टूर ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटरों तथा गोल्फ रिसॉर्ट का स्वामित्व रखनेवाली / परिचालन करनेवाली कंपनियों द्वारा मोटर कार, एसयूवी, सभी प्रयोजनों वाले वाहनों के आयात की अनुमति नहीं होगी।

• निर्यात दायित्व को बचाये गये शुल्क के छः गुना तक कम कर दिया गया है और निर्यात दायित्व को घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया है ।

• ईपीसीजी योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल की घरेलू प्राप्ति के लिए निर्यात दायित्व 10 प्रतिशत घटा दिया गया है ।

बाजार केन्द्रित योजना (एफएमएस), विशेष एफएमएस तथा उत्पाद केन्द्रित योजना

• नार्वे को एफएमएस के अंतर्गत शामिल किया गया है और वेनेज्युएला को विशेष एफएमएस के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

• 126 नये उत्पादों को एफपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया है जिनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, औषधि तथा टेक्सटाइल क्षेत्रों से मदें शामिल हैं ।

बाजार सम्बध्द उत्पाद केन्द्रित योजना (एमएलएफपीएस)

• एमएलएफपीएस को सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 61 तथा 62 के अंतर्गत सम्मिलित वस्त्रों के यूएसए तथा यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए 30 जून, 2014 तक बढ़ाया गया है ।

• इंजीनियरिंग, मोटर पुरजा तथा टेक्सटाइल क्षेत्रों से 47 नये उत्पादों को शामिल किया गया है ।

• ब्रुनेई तथा यमन को नये बाजार के रूप में शामिल किया गया है ।

भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस)

• एसएफआईएस की गणना अब सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित निवल मुक्त विदेशी मुद्रा के आधार पर की जाएगी ।

• सेवा निर्यातकों, जो विनिर्माण कार्यकलाप में भी लगे हैं, को पूंजीगत माल आयात करने/घरेलू रूप से प्राप्त करने के लिए एसएफआईएस स्क्रिप्स का प्रयोग करने की अनुमति है ।

• समूह कंपनियों के भीतर एसएफआईएस स्क्रिप्स की सीमित अंतरणीयता की अनुमति क्षेत्रीय प्रधिकारी द्वारा दी जाएगी ।

ब्याज उपदान योजना

• 2 प्रतिशत उपदान की गुंजाइश को इंजीनियरिंग क्षेत्र के 134 विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है ।

• इस योजना के लाभ को 31 मार्च, 2014 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहनीकरण योजना (आईईआईएस)

• यूएसए, यूरोपीय संघ तथा एशिया को निर्यात पर आईईआईएस के अंतर्गत उपलब्ध लाभ को वर्ष 2013-14 के लिए विस्तारित किया गया है ।

• लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के 53 देशों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

➢ विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)

• सेज इकाइयां स्थापित करने की शर्तों को न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल की आवश्यकता को कम करके और स्वामित्व में परिवर्तन की अनुमति देकर उदार बनाया गया है । इससे सेज इकाइयों में रुचि बढ़ने की उम्मीद है और यह लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र के लिए अधिक समावेश बनेगा ।

• भूमि की वर्तमान में न्यूनतम 100 एकड़ की आवश्यकता को घटाकर 50 एकड़ कर दिया गया है ।

• सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने आईटी/आईटीईएस सेज स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है ।

• सामान्य सुविधाएं निर्मित करने तथा परिचालित करने में बड़े पैमाने पर उत्पादन की किफायत प्राप्त करने के लिए और समग्र रूप में संकेन्द्रित उद्योग के लिए लागत में कमी लाने के लिए बाह्य बड़े पैमाने की किफायत उत्पन्न करने के लिए एक ही प्रकार की इकाइयों के समूहन (अर्थात् क्षेत्रीय विस्तारण) को प्रोत्साहित किया गया है ।

➢ विविध

• डम्पिंगरोधी शुल्क और सुरक्षा शुल्क के भुगतान की छूट शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) की अंतरणीयता के पृष्ठांकन के बाद उपलब्ध नहीं रहेगी ।

• पुनः जमा किये गये 4 प्रतिशत एसएडी स्क्रिपों के उपयोग की अनुमति 30 सितंबर, 2013 तक उपलब्ध होगी ।

• निर्यात दायित्व उन्मोचन प्रमाण-पत्र आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

• ऑनलाईन अनुपालन समाधान प्रणाली विकसित की गयी है ।

• आवेदन के साथ आईईसी तथा आरसीएमसी की भौतिक प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

• यदि निर्यात ईडीआई पोर्ट के माध्यम से किये जाते हैं तो ईओडीसी की मंजूरी के लिए एए, डीएफआईए के मामले में पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रति की हॉर्ड प्रति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

• एए/डीएफआईए तथा ईपीसीजी प्राधिकरण के लिए बैंक गारंटी / विधिक वचनपत्र के निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया हटा दी गयी है ।

• घर से कार्य की सुविधा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एसटीपीआई / ईओयू / बीटीपी/ ईएचटीपी के लिए प्रदान की गयी है ।

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्त्रोतों / माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रामाणिक हैं । प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रामाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है ।

नोट : भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है

1 करोड़ : 10 मिलियन

1 लाख : 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक,

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005

दूरभाष : +91-22-2217 2600
फैक्स : +91-22-2218 2572
ई-मेल : cag@eximbankindia.in
वेबसाइट : www.eximbankindia.in

संपर्क नंबर : अहमदाबाद : 079 2657 6852, बैंगलूरु : 080 2558 5755, चंडीगढ़ : 0172 2641 910, चेन्नै : 044 2852 2830, गुवाहाटी : 0361 2237607, हैदराबाद : 040 2330 7816, कोलकाता : 033 2289 1728, मुंबई : 022 2282 3320, नई दिल्ली : 011 2347 4800, पुणे : 020 2640 3000

अदिस अबाबा : + 251 116 - 630079, डकार : + 22 133 - 8232849, दुबई : + 9714 - 3637462, जोहॉनिस्बर्ग : + 2711 - 3265103, लंदन : + 44 20 - 73538830, सिंगापुर : + 65 65 - 326464, वॉशिंग्टन डी. सी. : + 1 202 - 2233238

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

जून 2013
खंड XXVII अंक II

एक्ज़िमिअस : निर्यात लाभ - फीड बैंक (प्रतिपुष्टि) फार्म

कृपया इसे और बेहतर बनाने में हमारी सहायता करें ।

1. आप किससे संबंधित हैं *(जो लागू हो उस पर टिक करें)*
   - ☐ सरकारी संस्था
   - ☐ गैर-सरकारी संस्था
   - ☐ कार्पोरेट
   - ☐ निर्यातक
   - ☐ शैक्षणिक संस्था
   - ☐ व्यक्तिगत
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

2. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आपके विचार
   - ☐ समझने में आसान एवं उपयोगी
   - ☐ थोड़ा सहायक
   - ☐ व्यापक
   - ☐ बिल्कुल उपयोगी नहीं

3. आप किस क्षेत्र में रूचि रखते हैं? *(कृपया टिक करें)*
   - ☐ क्षेत्रीय/औद्योगिक परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ देश/क्षेत्रीय परिदृश्य *कृपया उल्लेख करें*
   - ☐ व्यवसाय अवसर एवं संविदा
   - ☐ एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएँ
   - ☐ तिमाही समाचार
   - ☐ देशों का अवलोकन
   - ☐ मुद्रा की प्रवृत्तियाँ
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

4. क्या आप हमारे प्रकाशन से संतुष्ट हैं?
   - ☐ बेहद संतुष्ट
   - ☐ संतुष्ट
   - ☐ सामान्य
   - ☐ असंतुष्ट

5. क्या हमारा प्रकाशन आपके लिए उपयोगी रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ इसने काफी मदद की
   - ☐ यह उपयोगी रहा
   - ☐ कह नहीं सकते
   - ☐ यह उपयोगी नहीं रहा
   - ☐ अन्य *कृपया उल्लेख करें*.....

6. आपको हमारा प्रकाशन कब से मिल रहा है? *(किसी एक को चुनें)*
   - ☐ एक वर्ष से कम समय से
   - ☐ लगभग 1-3 वर्ष से
   - ☐ लगभग 3-5 वर्ष से
   - ☐ 5 वर्ष से अधिक समय से

7. आप यह प्रकाशन किस भाषा में चाहेंगे?
   - ☐ अंग्रेजी
   - ☐ हिन्दी

8. हमारे इस प्रकाशन के बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे?
   - ☐ हाँ
   - ☐ नहीं

   यदि हाँ, तो कृपया लिखें!

कृपया अपने सुझाव/फीडबैक हमें फैक्स/ई-मेल/डाक से निम्नलिखित पते पर भेजें : निगमित कार्य समूह, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केन्द्र संकुल, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फैक्स : +91-22 22182572, ई-मेल : cag@eximbankindia.in

नाम :_____

संपर्क विवरण :_____